PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 149
दि. 28.09.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

चुनाव आयोग पर बढ़ा दबाव, 2 अक्टूबर से राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान

नई दिल्ली। चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन मिलने से मामला और चर्चा में आ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से मुंबई से राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। वांगचुक ने इस आंदोलन के उद्देश्य का समर्थन किया है, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि किसी आंदोलन का समर्थन करने के लिए हर कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना आवश्यक नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से यह घोषणा ऐसे समय की गई है, जब चुनाव आयोग के भीतर फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर कथित आपत्तियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक और सार्वजनिक बहस तेज हुई है। रिपोर्टों के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज की थीं। इन मुद्दों में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और बहाल करने, फॉर्म-6 में बदलाव तथा चुनावी डेटा और तकनीकी व्यवस्था से जुड़े विषय शामिल बताए गए हैं।

इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर स्पष्टीकरण दिया है। आयोग का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े सभी आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से जारी किए गए थे। आयोग ने यह भी कहा कि एसआईआर से जुड़े उसके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन प्राप्त है। इस तरह एक ओर जहां आयोग के भीतर आपत्तियों को लेकर रिपोर्ट सामने आईं, वहीं आयोग ने महत्वपूर्ण फैसलों को सर्वसम्मत बताया है। एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पहले से ही राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर बहस चल रही है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से घर-घर सहायता उपलब्ध कराने और कुछ मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होने जैसे उपायों की जानकारी भी दी है। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अद्यतन और अधिक सटीक बनाने की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है।

इसी विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 25 सितंबर को घोषणा की थी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 2 अक्टूबर से मुंबई में प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और इसके बाद आंदोलन को देश के अन्य हिस्सों तक ले जाने की योजना है। पार्टी की ओर से चुनाव आयोग में जवाबदेही और चुनाव प्रक्रिया में सुधार की मांग उठाई जा रही है। सोनम वांगचुक ने आंदोलन के समर्थन को लेकर कहा कि किसी अभियान के समर्थन का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को हर स्थान पर जाकर स्वयं प्रदर्शन में शामिल होना पड़े। उनका कहना है कि आंदोलन अपने स्तर पर आगे बढ़ने चाहिए और यदि कई लोग किसी मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही और सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। 2 अक्टूबर को आंदोलन शुरू करने के फैसले का एक प्रतीकात्मक पक्ष भी है। यह दिन महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वांगचुक ने इस तारीख के महत्व का उल्लेख करते हुए इसे आंदोलनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी गांधी जयंती से अपने अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। आंदोलन मुंबई से शुरू होकर आगे अन्य शहरों तक ले जाने की बात कही गई है। चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों की खबरों ने इस पूरे विवाद को नया आधार दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार संधू और जोशी ने विभिन्न अवसरों पर आयोग के नाम से जारी कुछ फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची से जुड़े मामलों के अलावा चुनावी डेटा तक पहुंच और आयोग की तकनीकी प्रणालियों की निगरानी जैसे मुद्दे भी शामिल थे। हालांकि चुनाव आयोग ने इन घटनाक्रमों को आंतरिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए महत्वपूर्ण फैसलों पर तीनों आयुक्तों की सहमति की बात कही है।

इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आयोग ने हाल में संबंधित मुद्दों पर बैठक कर प्रक्रियात्मक और तकनीकी मामलों को लेकर कई फैसले किए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक 26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने बैठक की, जिसमें मतदाता पंजीकरण फॉर्म, चुनावी डेटाबेस तक पहुंच और तकनीकी व्यवस्था से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। यह बैठक उन रिपोर्टों के बाद हुई, जिनमें दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से पहले दर्ज की गई आपत्तियों का उल्लेख था।

विवाद के राजनीतिक असर का एक पहलू यह भी है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ विपक्षी दलों ने आयोग की जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, जबकि आयोग की ओर से अपने निर्णयों और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। इस कारण मामला केवल एक प्रस्तावित प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की संस्थागत कार्यप्रणाली को लेकर व्यापक बहस का रूप ले चुका है।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतदाता सूची में नाम जोड़ना, नाम हटाना, विवरण में संशोधन और अपील की व्यवस्था सीधे मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ी होती है। इसलिए इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, स्पष्ट नियम और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को लेकर उठने वाले सवाल सार्वजनिक महत्व रखते हैं। चुनाव आयोग की ओर से भी मतदाताओं की सुविधा और प्रक्रिया को लेकर कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं। अब 2 अक्टूबर की तारीख नजदीक आने के साथ निगाहें मुंबई में प्रस्तावित प्रदर्शन पर टिकी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी इसे देशव्यापी अभियान की शुरुआत के रूप में देख रही है, जबकि सोनम वांगचुक ने इसके जवाबदेही और चुनाव सुधार से जुड़े उद्देश्य का समर्थन किया है। उनके व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आने वाले दिनों में यह भी सामने आएगा कि आंदोलन का विस्तार किन शहरों तक होता है और चुनाव आयोग तथा अन्य राजनीतिक पक्ष इस अभियान पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं।

फिलहाल चुनाव आयोग से जुड़े विवाद में दो समानांतर तथ्य सामने हैं—एक ओर आयोग के दो सदस्यों की ओर से विभिन्न मुद्दों पर दर्ज आपत्तियों की रिपोर्ट है, वहीं दूसरी ओर आयोग का आधिकारिक पक्ष है कि एसआईआर समेत महत्वपूर्ण फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए। इसी पृष्ठभूमि में 2 अक्टूबर से प्रस्तावित प्रदर्शन चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर चल रही बहस को आगे बढ़ाने वाला घटनाक्रम बन गया है।

2000 रुपये से ज्यादा UPI भुगतान पर MDR के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

नई दिल्ली। 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को लेकर उठे कानूनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। अधिवक्ता अंजन दत्ता की ओर से दायर जनहित याचिका में केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए एमडीआर ढांचे को चुनौती दी गई है। 28 सितंबर की कार्यसूची के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।

याचिका का संबंध 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने वाले उस प्रावधान से है, जिसके तहत 2000 रुपये से अधिक के निर्धारित पर्सन-टू-मर्चेंट यानी पी2एम यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू किया जाना है। राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की ओर से अधिसूचित ढांचे के अनुसार ऐसे सामान्य श्रेणी के लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर निर्धारित किया गया है और प्रति लेनदेन अधिकतम शुल्क 300 रुपये तक सीमित रखा गया है। हालांकि पर्सन-टू-पर्सन भुगतान इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे।

याचिकाकर्ता ने नए शुल्क ढांचे की कानूनी प्रक्रिया और उसके आधार पर सवाल उठाए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि

एमडीआर की व्यवस्था पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा, पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श के बिना लाई गई। याचिका में केंद्र सरकार की ओर से 14 सितंबर को जारी अधिसूचना और 15 सितंबर को घोषित एमडीआर ढांचे को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले संबंधित पक्षों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था। मामले में 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' की संशोधित धारा 10-ए की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाया गया है। याचिका के अनुसार, इस प्रावधान के जरिए कार्यपालिका को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अलग-अलग माध्यमों के लिए शुल्क से जुड़ी व्यवस्था तय करने का अधिकार मिलता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने इसी आधार पर संशोधित प्रावधान की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा की मांग की है। याचिका में यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के बीच शुल्क व्यवस्था में अंतर का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक नए ढांचे में रुपे डेबिट कार्ड के लिए शून्य एमडीआर की सुरक्षा अलग तरीके से जारी रखी गई है, जबकि 2000 रुपये से अधिक के निर्धारित यूपीआई व्यापारी भुगतान को नए शुल्क ढांचे में शामिल किया गया है। याचिका में दोनों डिजिटल भुगतान माध्यमों के साथ अलग-अलग व्यवहार के कानूनी आधार पर भी सवाल उठाया गया है। सरकार की ओर से घोषित व्यवस्था में यह स्पष्ट किया गया है कि एमडीआर सरकार या एनपीसीआई की ओर से वसूला जाने वाला कर नहीं है। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह शुल्क भुगतान व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पक्षों, जैसे बैंक और भुगतान एप्लिकेशन प्रदाताओं के बीच वितरित होता है। सरकार ने यह भी कहा है कि व्यक्ति से व्यक्ति होने वाले यूपीआई लेनदेन पर किसी भी राशि के लिए एमडीआर नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह 2000 रुपये तक के व्यापारी भुगतान और शून्य-एमडीआर व्यवस्था के तहत आने वाले छोटे व्यापारियों के लेनदेन को भी शुल्क से बाहर रखा गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नए ढांचे से करीब 96 प्रतिशत पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआई लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे। एमडीआर केवल निर्धारित श्रेणी के 2000 रुपये से अधिक के व्यापारी लेनदेन पर लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि रोजमर्रा के छोटे डिजिटल भुगतान और व्यक्ति से व्यक्ति होने वाले सामान्य यूपीआई हस्तांतरण पहले की तरह शुल्क-मुक्त रहेंगे। नए ढांचे में कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए अलग शुल्क व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। समाचार एजेंसी आकाशवाणी के अनुसार रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे कुछ क्षेत्रों में 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर पांच रुपये का फ्लैट एमडीआर रखा गया है, जबकि पूंजी बाजार से जुड़े कुछ लेनदेन पर अलग दर निर्धारित है। इस व्यवस्था का अंतिम प्रभाव संबंधित व्यापारी श्रेणी और लेनदेन के प्रकार पर निर्भर करेगा। एमडीआर व्यवस्था को लेकर कारोबारियों और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में भी चर्चा तेज हो गई है। एक ओर सरकार और भुगतान क्षेत्र की ओर से इसे यूपीआई व्यवस्था की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यापारी संगठनों ने अधिक मूल्य के यूपीआई भुगतान पर शुल्क को लेकर चिंता जताई है।

रेगिस्तान में मिला दुर्लभ मेहमान, भारत में पहली बार सिस्तान सैंड बोआ की वैज्ञानिक पुष्टि

सीकर। राजस्थान के शुष्क भूभाग में वन्यजीवों की विविधता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खोज सामने आई है। सीकर जिले के रामगढ़-शेखावाटी क्षेत्र में सिस्तान सैंड बोआ नामक सांप की मौजूदगी की भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से पुष्टि हुई है। यह प्रजाति जहरीली नहीं है और अपने मोटे शरीर तथा रेगिस्तानी वातावरण में रहने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इससे पहले सिस्तान सैंड बोआ के ईरान और पाकिस्तान में पाए जाने की जानकारी थी। राजस्थान में मिले नमूनों की वैज्ञानिक जांच के बाद अब भारत के सरीसृप जैव-विविधता के रिकॉर्ड में भी इस प्रजाति का नाम जुड़ गया है।

इस खोज में वन्यजीव शोधकर्ता विवेक शर्मा और रणथंभौर के वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खंडाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शोधकर्ताओं ने वर्ष 2025 में सीकर जिले के अलग-अलग स्थानों से सिस्तान सैंड बोआ के तीन नमूने खोजे। पहला सांप 19 अगस्त को एक गौशाला में मिला था। इसके बाद 12 सितंबर को सुंडा की ढाणी में एक घर के आंगन से दूसरा नमूना मिला। तीसरा सांप 21 सितंबर को रुकनसर में एक निर्माणाधीन मकान के पास देखा गया। तीनों नमूनों के अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं ने इनके शरीर की संरचना, रंग, शल्कों और अन्य शारीरिक विशेषताओं का विस्तृत परीक्षण किया।

वैज्ञानिक पहचान की प्रक्रिया में केवल सांप का सामान्य रूप या तस्वीर पर्याप्त नहीं होती। कई सरीसृप प्रजातियां बाहरी तौर पर एक-दूसरे से काफी मिलती-जुलती हैं, जिसके कारण उनके बीच अंतर करना विशेषज्ञों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सिस्तान सैंड बोआ के मामले में भी यही स्थिति सामने आई। राजस्थान में लंबे समय से इस तरह के सांप देखे जाने की सूचनाएं मिलती रही थीं, लेकिन उनकी प्रजाति को लेकर निश्चित वैज्ञानिक निष्कर्ष उपलब्ध नहीं था। मिले नमूनों के शारीरिक लक्षणों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं ने इनकी पहचान सिस्तान सैंड बोआ के रूप में की। इस खोज से संबंधित शोध 26 मई 2026 को 'जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा' में प्रकाशित हुआ। वैज्ञानिक शोध के प्रकाशित होने के साथ ही भारत में इस प्रजाति की मौजूदगी को औपचारिक वैज्ञानिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। इससे पहले इसके भारत में होने की संभावना को लेकर जानकारी और तस्वीरें सामने आती रही थीं, लेकिन किसी संरक्षित नमूने के आधार पर प्रजाति की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई थी।

सिस्तान सैंड बोआ का आकार और शरीर इसे भारत में पाए जाने वाले कुछ अन्य बोआ प्रजातियों से अलग पहचान देने में मदद करता है। इसका शरीर अपेक्षाकृत मोटा होता है और यह सूखे तथा रेतीले इलाकों में रहने के अनुकूल माना जाता है। शुष्क क्षेत्रों में जमीन के भीतर या उसके आसपास रहने वाले ऐसे सांप अपने वातावरण के अनुसार व्यवहार और शारीरिक संरचना विकसित करते हैं। जहरीला नहीं होने के कारण यह सांप इंसानों के लिए विषैले सांपों जैसी चुनौती नहीं माना जाता, हालांकि किसी भी जंगली सरीसृप को पकड़ने या उसके साथ छेड़छाड़ करने से बचना जरूरी है।

सिस्तान सैंड बोआ देखने में भारत में पाए जाने वाले लाल सैंड बोआ से काफी मिलता-जुलता है। यही समानता लंबे समय तक इसकी सही पहचान में कठिनाई का कारण भी बन सकती है। दोनों प्रजातियों में अंतर करने के लिए शरीर के कई लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन पूंछ की बनावट एक उपयोगी पहचान विशेषता मानी जाती है। सिस्तान सैंड बोआ की पूंछ शरीर से आगे बढ़ते हुए धीरे-धीरे पतली होती जाती है और अंत में नुकीले सिरे पर समाप्त होती है। इसके विपरीत लाल सैंड बोआ की पूंछ काफी हिस्से तक अपेक्षाकृत मोटी रहती है और इसके बाद पतली होती है। विशेषज्ञों ने इसी तरह के शारीरिक अंतर समेत अन्य लक्षणों के आधार पर मिले नमूनों की पहचान की। वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खंडाल के अनुसार, राजस्थान में इस तरह के सांपों को लेकर जानकारी कई वर्षों से सामने आती रही है। राज्य के लगभग 40 स्थानों से ऐसे सांपों की तस्वीरें शोधकर्ताओं तक पहुंच चुकी थीं। हालांकि तस्वीरों के आधार पर किसी प्रजाति की अंतिम वैज्ञानिक पुष्टि करना संभव नहीं होता। इसके लिए नमूने की शारीरिक विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक होता है। इसी वजह से पहले सामने आई तस्वीरों को संभावित संकेत के रूप में देखा गया, लेकिन उन्हें सिस्तान सैंड बोआ की आधिकारिक पुष्टि का आधार नहीं बनाया जा सका।

चूरू जिले में भी वर्ष 2003 और 2006 के दौरान इस तरह के सांपों की तस्वीरें लिए जाने की जानकारी सामने आई है।

आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का नया अध्याय बनी सर्जिकल स्ट्राइक : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' के 138वें संस्करण में वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हुए कहा कि इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दुनिया के सामने एक नए रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों के कारण देश ने लंबे समय तक जिस पीड़ा और चुनौती का सामना किया, सर्जिकल स्ट्राइक उस पीड़ा के खिलाफ भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति और प्रतिक्रिया को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है।

प्रधानमंत्री का यह संबोधन ऐसे समय आया है जब 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के दस वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में याद किया। उनके अनुसार, दस वर्ष पहले भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने के भारत के दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट रूप से सामने रखा।

मोदी ने कहा कि आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक प्रभावित किया है। एक दौर ऐसा भी रहा जब देश के विभिन्न हिस्सों में सिलसिलेवार बम धमाकों की घटनाएं सामने आती थीं और आम नागरिकों के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती थी। उन्होंने इसी संदर्भ में सितंबर 2008 में दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का उल्लेख किया। इसके कुछ ही सप्ताह बाद मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले को भी

प्रधानमंत्री ने याद किया। इन घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने आतंकवाद से देश को हुई मानवीय और सामाजिक क्षति की ओर ध्यान दिलाया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को केवल एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में आए बदलाव का भी संकेत थी। उनके मुताबिक, इस कार्रवाई के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बीते दस वर्षों के दौरान देश ने अलग-अलग मौकों पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया के जरिए यह संदेश दिया है कि आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए भारत दृढ़ता के साथ कार्रवाई करेगा।

28-29 सितंबर 2016 की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के जवानों के साहस को भी याद किया। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने वाली इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। सर्जिकल स्ट्राइक के दस वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।

मोदी ने अपने संबोधन में इसके बाद की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक और हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कई मौकों पर अपनी नीति को स्पष्ट किया है। प्रधानमंत्री के अनुसार, आतंकवादियों द्वारा भारत को निशाना बनाए जाने की स्थिति में देश की ओर से कड़ा जवाब देने का संदेश लगातार दिया गया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से जोड़ते हुए पिछले वर्षों में हुए विभिन्न अभियानों का संदर्भ दिया।

प्रधानमंत्री ने आतंकवादी घटनाओं के पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि देश ने लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है। दिल्ली के 2008 के धमाकों और मुंबई के 26/11 हमले का उल्लेख इसी क्रम में किया गया। इन घटनाओं ने देश की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद से निपटने की रणनीति के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी की थीं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इन घटनाओं की स्मृति देश को आतंकवाद के खिलाफ सतर्क और एकजुट रहने की आवश्यकता का भी एहसास कराती है।

'मन की बात' में सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख प्रधानमंत्री ने उस समय किया जब इस कार्रवाई की दसवीं वर्षगांठ सामने है। 2016 में हुई इस कार्रवाई के बाद से भारतीय सुरक्षा और विदेश नीति के संदर्भ में इसे लगातार महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसी ऐतिहासिक संदर्भ को सामने रखते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख समय के साथ अधिक स्पष्ट हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल किसी एक घटना या अभियान तक सीमित नहीं है। इसके लिए लगातार सतर्कता, सुरक्षा तैयारियों और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। उन्होंने पिछले दशक में हुई कार्रवाइयों को इसी व्यापक संदर्भ में रखा। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर तक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति की निरंतरता को रेखांकित किया।

सर्जिकल स्ट्राइक की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री का यह उल्लेख 2016 की उस कार्रवाई को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति के संदर्भ में केंद्र में ले आया है। 28-29 सितंबर 2016 को हुई कार्रवाई की वर्षगांठ के साथ उस दौर की घटनाओं, देश की सुरक्षा चुनौतियों और उसके बाद अपनाए गए कदमों पर भी चर्चा तेज होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पुराने आतंकी हमलों की पीड़ा को याद करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक को उस दौर के अनुभवों की पृष्ठभूमि में भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया।

संपादकीय

ट्रंप की दुनिया में नाम बदलने से लेकर नक्शे बदलने तक

डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को समझना हो तो शायद पुराने राजनीतिक शब्दकोश को कुछ समय के लिए किनारे रखना पड़ेगा। उनकी शैली में विस्तारवाद भी है, व्यापारिक सौदेबाजी भी है, दबाव की राजनीति भी है और सबसे बढ़कर अपनी बात को दुनिया के सामने बड़े आत्मविश्वास से रखने की कला भी है। इसलिए कभी-कभी यह समझना मुश्किल हो जाता है कि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं या किसी ऐसे शासक की तरह, जिसे दुनिया का नक्शा अपनी पसंद के हिसाब से दोबारा बनाने का अधिकार मिल गया हो। कनाडा को अमेरिका का संभावित 51वां राज्य बताने से लेकर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की इच्छा व्यक्त करने तक ट्रंप ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं, जिन्होंने पारंपरिक कूटनीति को चुनौती दी है। सामान्य तौर पर राष्ट्रों के बीच सीमाएं इतिहास, संधियों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों से तय होती हैं, लेकिन ट्रंप की राजनीति में कभी-कभी ऐसा लगता है कि भूगोल भी बातचीत की मेज पर रखा कोई व्यावसायिक सौदा है। पसंद आया तो दावा कर दिया, जरूरत लगी तो दबाव बना दिया और अवसर मिला तो उसे अमेरिकी हित से जोड़ दिया। गाजा को लेकर भी ट्रंप की प्रस्तावित योजना ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काफी चर्चा पैदा की थी। युद्ध से तबाह इलाके को खाली कराकर उसे एक बड़े पर्यटन केंद्र में बदलने की उनकी कल्पना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। इस विचार ने यह सवाल खड़ा किया कि किसी क्षेत्र के भविष्य का फैसला वहां रहने वाले लोगों की इच्छा और अधिकारों के आधार पर होना चाहिए या किसी बाहरी शक्ति की विकास संबंधी कल्पना के आधार पर। यही सवाल ट्रंप की विदेश नीति के दूसरे प्रस्तावों पर भी लागू होता है। अब होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रसंग भी इसी व्यापक तस्वीर में देखा जा सकता है। यह कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है। फारस की खाड़ी से दुनिया के दूसरे हिस्सों तक ऊर्जा की आपूर्ति में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस क्षेत्र को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तक पहुंच सकता है। यहीं से व्यंग्य का वह हिस्सा शुरू होता है जिसमें ट्रंप की शैली को भारत में होने वाले नामकरण अभियान से जोड़कर देखा जा सकता है। हमारे यहां किसी शहर, जिले, सड़क या स्टेशन का नाम बदलते ही राजनीति गरम हो जाती है। नाम के साथ इतिहास जुड़ा होता है, पहचान जुड़ी होती है और कई बार भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। इसलिए नाम बदलना महज प्रशासनिक फैसला नहीं माना जाता। यह अपने आप में एक राजनीतिक संदेश बन जाता है।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में कई स्थानों के नाम बदले गए हैं और इस विषय पर लगातार राजनीतिक बहस होती रही है। समर्थकों का तर्क रहा है कि इससे पुराने नामों की जगह ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पहचान को सामने लाया जा रहा है, जबकि आलोचक इसे राजनीतिक प्रतीकवाद से जोड़ते रहे हैं। लेकिन इस पूरी बहस ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि नक्शे पर लिखा हुआ नाम भी राजनीति का हथियार बन सकता है। यही कारण है कि ट्रंप की शैली को मजाकिया अंदाज में 'योगीकरण' कहने का विचार पैदा होता है। अंतर बस इतना है कि यहां चर्चा शहरों और जिलों के नामों की होती है और वहां दुनिया के रणनीतिक क्षेत्रों को लेकर दावे और घोषणाएं अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती हैं। यानी नामकरण का दायरा छोटा-बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके पीछे मौजूद राजनीतिक संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन का उदाहरण भी इस संदर्भ में अक्सर सामने आता है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के लिए अपने अनुसार नाम जारी किए हैं। भारत ने इन दावों और नामकरण की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया है। साफ है कि किसी स्थान को नया नाम देने भर से उसकी वास्तविक स्थिति नहीं बदलती। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रतीकों की अपनी भूमिका होती है। नाम बदलने की कोशिश कई बार उस भूभाग पर राजनीतिक दावा जताने का तरीका बन जाती है। ट्रंप की राजनीति में भी प्रतीकों का इस्तेमाल खूब दिखाई देता है। वह छोटी बात को भी बड़े राजनीतिक संदेश में बदलने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका पहले से ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में शामिल है, लेकिन ट्रंप की भाषा में अमेरिकी शक्ति को और अधिक स्पष्ट, आक्रामक और प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उनके लिए 'अमेरिका पहले' केवल आर्थिक नीति का नारा नहीं, बल्कि विदेश नीति को देखने का भी एक नजरिया है।

विश्वविद्यालयों में नयी ऊर्जा संचार का वक्त

> उच्च शिक्षा का लक्ष्य आज्ञाकारी नागरिकों को फ़ैक्टरी की तरह तैयार करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का अस्तित्व जरूरी है। जहां विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता, सहिष्णुता और आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। वहीं राजनीतिक दखल, शिक्षा का बाजारीकरण और निजीकरण ऐसे संस्थानों के लिए नुकसानदेह हैं।

असहिष्णुता के इस दौर में, परेशान करने वाला ख्याल मेरे मन में आ रहा है। क्या राजनीतिक प्रतिष्ठान को अब बौद्धिक रूप से जीवंत और शैक्षणिक रूप से समृद्ध, समावेशी सरकारी विश्वविद्यालयों की अहमियत और अधिक महसूस नहीं हो रही? अन्यथा, हमारे कुछ प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालयों पर लगातार हो रहे हमलों को कैसे लिया जाए? मसलन, जाधवपुर यूनिवर्सिटी का हालिया उथल-पुथल भरा घटनाक्रम - जो शायद पश्चिम बंगाल का सबसे जाना-माना शैक्षणिक संस्थान है।

ऐसा लगता है कि बंगाल की बीजेपी सरकार इस विश्वविद्यालय के राजनीतिक-सांस्कृतिक माहौल से ख़ास तौर पर ख़ुश नहीं। इसमें हैरानी की बात नहीं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी छात्र समूहों के बीच तनाव के बाद हिंसक झड़पें और आधी रात को तोड़-फोड़ होते हमें देखने को मिलीं। हमने भगवा मार्च और यूनिवर्सिटी गेट के सामने नागा साधुओं की मौजूदगी भी देखी। क्या अपनी ख़ास शारीरिक भंगिमाओं से ये साधु उन छात्रों और शिक्षकों को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था समस्याग्रस्त या अनैतिक असहमति रखने वाला मानती है?वास्तव में, हालिया समय में हमारे प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालयों पर हो रहे इस प्रकार के हमलों का कोई अंत नहीं दिख रहा है- जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ तक; या जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक। टकराव नाना रूप धर कर सामने आ रहे - कुलपति नियुक्ति के तरीके से लेकर ज्ञान की नई राजनीति तक -वह जिसे 'भारतीय ज्ञान प्रणाली' कहा जा रहा है - ऐसा होने देकर आलोचनात्मक सोच व शैक्षणिक आजादी के माहौल को ख़त्म करने तक। हो सकता

है हमारे प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का सुनियोजित पतन एक नए कारोबार के बढ़ने का आधार भी बना रहा हो-तेज़ी से बढ़ रहे निजी विश्वविद्यालयों के ज़रिए शिक्षा का बाज़ारीकरण (यानी शिक्षा को बिकाऊ चीज़ बनाना)।

भले ही नव-उदारवाद के समर्थक - या वे लोग जो मुनाफ़े की समान सोच के साथ शिक्षा को भी पॉपकॉर्न की भांति बेचते हैं - हमारे बेहतरीन सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के गिरते मूल्य पर आंसू न बहाएं, लेकिन वे सभी लोग, जिनकी ज़िंदगी इन संस्थानों की वजह से बदली है, उन्हें आगे आना चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। निजी तौर पर मैं सदा दो बेहतरीन सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों का आभारी रहूंगा - कोलकाता का प्रेसीडेंसी कॉलेज और दिल्ली की जेएनयू।

लेखक के मुताबिक- मैं अच्छे प्रोफ़ेसरों, एक जीवंत शैक्षणिक संस्कृति, सार्थक बहस, संवाद एवं राजनीतिक मंथन के अनुकूल माहौल में और, सबसे बढ़कर, सामाजिक विविधता के समृद्ध अनुभव से पल्लवित होकर बड़ा हुआ हूं। लगता है कि वहां विशेषज्ञतापूर्ण अकादमिक ज्ञान अर्जित करने के अलावा, मैंने तीन ज़रूरी बातें सीखीं, जो मेरे हिसाब से एक लोकतांत्रिक, समावेशी व काफ़ी हद तक बराबरी वाले समाज के विकास के लिए ज़रूरी हैं। सर्वप्रथम, मैंने (लेखक) अनेकता और मिल-जुलकर रहने की भावना को समझा। एक तमिल लड़का, एक मिज़ो लड़की, बिहार के दूर-दराज़ इलाके से आए एक दलित छात्र या केरल की एक होनहार मुस्लिम छात्रा के साथ बड़े होने के दौरान, मैंने दूसरों की भावनाओं को समझने (सहानुभूति), अलग-अलग संस्कृतियों के बीच संवाद बनाने और, सबसे बढ़कर, यह समझने की संवेदनशीलता सीखी कि भारतीय होने का असल मतलब अनिवार्य रूप से हमारी गौरवशाली अनेकता और विविधता के बीच दूसरों की बातों को गहराई से सुनने की कला विकसित करना है। कदाचित, एक बेहतरीन सार्वजनिक यूनिवर्सिटी का यह अनकहा सबक ही हमें धार्मिक कट्टरपंथ, विदेशियों के प्रति नफ़रत रखने वाली राष्ट्रवादी सोच और संकीर्ण पहचान की राजनीति को हमेशा शक की नज़र से देखने के क़ाबिल बना गया।

दूसरी बात, मैंने सीखा कि नव-उदारवाद या बाज़ार-केंद्रित मूलभूत सोच की भी अपनी सीमाएं होती हैं। हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। शिक्षा का अधिकार किसी एक वर्ग-विशेष का हक और आर्थिक पूंजी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। किफ़ायती और अच्छी गुणवत्ता वाले सरकारी विश्वविद्यालय के बिना, हम उस बुराई का विरोध नहीं कर पाएंगे, जो सदियों से चली आ रही है - यानी सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का लगातार बने रहना। कई बार मुझे लगता है कि मैं क़िस्मत वाला था कि मेरे बड़े होने के दौरान बढ़िया सरकारी विश्वविद्यालय मौजूद थे; वर्ना, मेरे माता-पिता के लिए मुझे बहुत महंगे और बाज़ारीकृत 'फाइव-स्टार' निजी विश्वविद्यालयों में भेजना और हर साल लगभग 13 लाख रुपये का इंतज़ाम करना नामुमकिन होता!

और तीसरी बात, मैंने सीखा कि लोकतंत्र समय-समय पर चुनाव करवाए जाने की रस्म-अदायगी भर नहीं है। सोचने, काम करने और जीने के तरीक़े वाला लोकतंत्र बनाने के लिए आलोचनात्मक सोच की भावना होना ज़रूरी है- यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो करते हैं, या वे जिन आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियों को बढ़ावा देते हैं, उनके असर को परखने और समझने की क्षमता होना। लोकतंत्र का मतलब विरोध की संस्कृति या प्रतिरोध की कला भी है। हम यह कैसे भूल सकते हैं कि इसी प्रतिरोध की संस्कृति के ज़रिए ही हम नस्लवाद, रंगभेद, उपनिवेशवाद, जातिवाद, छुआछूत, गरीबी, पितृसत्ता, धार्मिक कट्टरपंथ और फासीवाद से आगे बढ़ पाए हैं?

इसलिए, एक बढ़िया विश्वविद्यालय में, जब युवा छात्र नेल्सन मंडेला, ज्योतिराव फुले, सिमोन द बोउवार, मोहनदास करमचंद गांधी और रचनात्मक असहमति रखने वाले कई अन्यों के बारे में पढ़ते हैं, या पॉल रॉबसन को याद करते हुए 'वी शैल ओवरकम...' (हम होंगे कामयाब...) गाते हैं, तो यह सिर्फ़ उनके अकादमिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं होता; असल में, इस प्रकार का बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव उन्हें सशक्त बनाता है और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध, बौद्धिक रूप से जागरूक और राजनीतिक रूप से सतर्क नागरिकों के तौर पर जीने के लिए प्रेरित करता है।

यह एक ज़रूरी सबक है, ख़ासकर तब जब बाज़ार-केंद्रित सोच रखने वाली और हावी हुई विचारधारा शिक्षा की कीमत को केवल 'नौकरी और तनख़्वाह' के नज़रिए से मापती हो। इसकी बजाय, आलोचनात्मक सोच और आज़ादी-पसंद राजनीति के इस पहलू पर बार-बार ज़ोर दिया जाना चाहिए, ख़ासकर तब जब सामाजिक रूढ़िवाद का एक नया रूप (जो उग्र धार्मिक राष्ट्रवाद की विचारधारा की ख़ासियत लिए है) असहमति रखने वाले हर व्यक्ति को 'दिमागी नक्सल' या 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' का सदस्य ठहराकर बदनाम करता हो!

यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक लोकतांत्रिक समाज के लिए बढ़िया एवं उदार सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की ज़रूरत होती है। आख़िरकार, उच्च शिक्षा का मक़सद केवल ऐसे आज्ञाकारी नागरिक तैयार करना भर नहीं है, जो मानो किसी फ़ैक्टरी में ढले हों, या जो केवल टेक्नो-कॉरपोरेट साम्राज्य के लिए 'तकनीकी कुशल कार्यबल' तैयार करती हो। विश्वविद्यालय ऐसे जागरूक नागरिक भी तैयार करे, जिनकी आंखों में अभी भी एक न्यायपूर्ण और मानवीय दुनिया का सपना हो।

प्रेरणा

सड़क के उस पार

हमारे घर के ठीक सामने उनका घर था। दोनों घरों के बीच बस एक सड़क थी, मगर समय के साथ वही सड़क इतनी चौड़ी हो गई थी कि उसे पार करना जैसे किसी खाई को पार करना हो। पूरे मोहल्ले में हमारे जैसे भारतीय मूल के केवल दो परिवार थे—एक उनका और दूसरा हमारा। बाकी सभी घरों में गोरे परिवार रहते थे।

गर्मियों की शामों में मोहल्ले के गोरे लोग अपने घरों से निकलकर सड़क किनारे जमा हो जाते। कोई हंसता, कोई बातचीत करता, कोई दिनभर की थकान उतारता। कई बार मैं भी उनके पास जाकर खड़ा हो जाता। मुझे देखते ही उनकी बातचीत अचानक धीमी पड़ जाती। हंसी गायब हो जाती और कुछ ही क्षणों में वे अपने-अपने घरों की ओर लौटने लगते। शायद मेरी सांवली त्वचा उन्हें उनकी बनाई हुई दुनिया की सीमा याद दिला देती थी।

मुझे अक्सर आश्चर्य होता कि सामने रहने वाले सुरिंदर के परिवार का कोई सदस्य भी कभी उनके बीच क्यों नहीं जाता। शायद वे भी समझ चुके थे कि पड़ोस में रहने और समाज का हिस्सा होने में फर्क होता है।

हमारे घर जब कोई रिश्तेदार पहली बार आता तो लगभग हर व्यक्ति यही पूछता, "आस-पास अपने लोगों का कोई घर है?"

मैं सामने वाले घर की ओर हाथ कर देता, "वह रहा। वे भी अपने ही लोग हैं।"

रिश्तेदार प्रसन्न होकर कहते, "अच्छा है। पड़ोस में अपने लोग हों तो सुख-दुख में बड़ा सहारा रहता है।"

उन्हें क्या पता था कि इन दो घरों के बीच केवल सड़क नहीं, जाति की एक अदृश्य दीवार भी खड़ी हो चुकी थी। एक समय ऐसा नहीं था। मेरी मां और सुरिंदर की मां में अच्छी बातचीत थी। दोपहर में जब दोनों घरों के पुरुष काम पर चले जाते और बच्चे अपनी-अपनी व्यस्तताओं में होते, तो दोनों महिलाएं कभी हमारे घर बैठकर ऊन से स्वेटर बुनतीं, कभी सामने वाले घर चली जातीं। उनके बीच घरेलू बातें होतीं, हंसी-मजाक होता। सुरिंदर के पिता से भी हमारे घरवालों की सामान्य दुआ-सलाम थी। फिर सब कुछ बदल गया।

सुरिंदर और मैंने जब अपने परिवारों से विवाह की इच्छा बताई तो जैसे दोनों घरों के बीच खिंची सड़क पर अचानक कांटे उग आए। उनके घर से हमारे यहां आना बंद हो गया और हमारे घर से उनके यहां जाना।

सुरिंदर जिस छोटी-सी फैक्टरी में रजाइयां सिलती थी, वह मेरे कार्यालय के पास थी। दोनों जगहों पर लंच का समय लगभग एक ही था। धूप वाले दिनों में कर्मचारी बाहर निकलकर बैठते। कोई आंखें बंद करके धूप सेंकता, कोई अपना खाना खाता और कोई अखबार पढ़ता।

इन्हीं दोपहरों में हमारी दोस्ती गहरी हुई थी।

हम अक्सर भारत की बातें करते। वह भारत में पैदा हुई थी, वहीं पढ़ी-बढ़ी थी। मैं भी उसी मिट्टी से आया था। वह समाज में जाति और ऊंच-नीच की खाई को लेकर परेशान रहती। भारत में होने वाले सांप्रदायिक तनावों की बातें करते हुए उसकी आवाज में चिंता होती। हम दोनों की सोच मिलती थी। धीरे-धीरे बातचीत दोस्ती बनी और दोस्ती कब जीवन के निर्णय तक पहुंच गई, पता ही नहीं चला।

सुरिंदर अपने परिवार के प्रति बेहद जिम्मेदार थी। उसके घर में कमाने वालों में वह और उसके पिता ही थे। उसकी मां घर पर स्वेटर और ऊन का काम कर थोड़ी-बहुत आमदनी कर लेती थीं। सुरिंदर उन्हें बाहर काम करने नहीं देना चाहती थी। उसका छोटा भाई पढ़ाई करता था और घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। मैं उसकी समझदारी से प्रभावित था।

एक दिन मैंने हंसते हुए कहा, "तू इतनी समझदार कब से हो गई?"

वह मुस्कराकर बोली, "तेरे साथ रहकर।"

शायद उसी दिन हम दोनों ने मन ही मन तय कर लिया था कि जिंदगी भी साथ बितानी है।

लेकिन परिवारों की अपनी दुनिया होती है। मां-बाप की सहमति हमारे लिए जरूरी थी। मैंने घर में बात रखी तो मां की आंखों में उम्मीदों की जगह चिंता उतर आई।

"इतने अरमानों से इकलौते बेटे को पाला है। सोचा था, शादी में सारे शौक पूरे करूंगी।"

मैंने कहा, "तो कर लो। सुरिंदर में कमी क्या है?"

मां ने तुरंत जाति का सवाल खड़ा कर दिया। वह जुलाहे परिवार की बेटी थी और हम जट्ट थे। अचानक उसकी सारी अच्छाइयां एक तरफ हो गईं और उसकी जाति दूसरी तरफ।

पिता ने भी कहा कि बिरादरी क्या कहेगी। बहन ने मुझे समझाया कि जिंदगी केवल अपनी इच्छा से नहीं चलती, माता-पिता की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है।

मैंने पूछा, "अगर वह अच्छी पत्नी बन सकती है तो अच्छी बहू क्यों नहीं? हम ऊंचे और वह नीची क्यों?"

मेरे सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन मेरी बात स्वीकार करने की इच्छा भी किसी में नहीं थी।

उधर सुरिंदर के घर में भी यही हुआ। उसे भी रिश्तेदारों के तानों और समाज की बदनामी का डर दिखाया गया। दो परिवार, दो घर, दो अलग दिशाओं में खड़े लोग—और बीच में वही सड़क।

कई बार मैं अपने घर के कमरे में खड़ा होकर सामने वाले घर की खिड़की देखता। वहां की चीजें साफ दिखाई देती थीं, मगर वहां रहने वाले लोग अचानक बहुत दूर हो गए थे। सुरिंदर की मां मुझे देखते ही परदे गिरा देतीं। उनके घर में गुरु नानक देव जी की तस्वीर लगी थी। हमारे घर में भी वही तस्वीर थी।

मैं सोचता—हम दोनों सिख हैं, दोनों पंजाबी हैं, दोनों एक ही देश से आए हैं। हमारे धार्मिक विश्वास एक हैं, हमारी भाषा एक है, हमारी यादें एक हैं। फिर सिर्फ जाति ने हमें इतना अलग कैसे कर दिया?

एक रात अचानक दोनों घरों में खलबली मच गई। किसी ने शरारत करते हुए हमारी और उनकी कारों के शीशे तोड़ दिए। दोनों परिवार सड़क पर आ गए। पिता पुलिस को सूचना देने और नस्ली भेदभाव के खिलाफ काम करने वाले संगठनों से संपर्क करने की बात करने लगे। मेरी मां और सुरिंदर की मां भी पहली बार लंबे समय बाद साथ खड़ी थीं।

"दूसरे किसी घर को नुकसान नहीं हुआ," मेरी मां ने कहा, "हमारे ही दोनों घर निशाना बने हैं।"

सुरिंदर की मां बोलीं, "कुछ लोगों को हमारा यहां आकर बसना और ठीक-ठाक रहना भी पसंद नहीं।"

उस क्षण मुझे लगा जैसे दोनों घरों के बीच खड़े सारे कांटे किसी ने कुचल दिए हों। जिस बाहरी भेदभाव ने हमें एक साथ खड़ा कर दिया था, उसने हमारे भीतर का भेद भी कुछ देर के लिए छोटा कर दिया।

अगली सुबह मुझे काम पर जाना था। सुरिंदर की कार के शीशे टूटे होने के कारण मैंने उसके पिता से कहा, "मैं इसे अपने साथ छोड़ देता हूं।"

संवेदना के साथ न्याय भी सुनिश्चित हो

आईआईटी बांबे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या एक गहरी मानवीय त्रासदी है। एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, सहपाठी सदमे और आक्रोश में हैं, परिसर के भीतर भरोसा टूटा है और एक शिक्षक आरोपों के घेरे में है। ऐसे क्षण में संवेदना, संयम और निष्पक्षता तीनों की आवश्यकता है। किसी की पीड़ा को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन पीड़ा को प्रमाण भी नहीं बनाया जा सकता। संस्थान की प्रतिष्ठा आरोपों पर पर्दा डालने का बहाना नहीं हो सकती और केवल आरोप लग जाने से किसी को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले की निष्पक्ष जांच ही सत्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। किसी छात्र की आत्महत्या को राजनीति का रंगमंच नहीं बनने देना चाहिए।

टीवी की उत्तेजक बहसें, डिजिटल मीडिया पर तत्काल फैसले और दोष सिद्ध होने से पहले गिरफ्तारी अथवा दोषमुक्ति की मांग- ये सब सत्य की खोज को कठिन बनाते हैं। आत्महत्या समाज और संस्थान के लिए आत्ममंथन का क्षण है। आईआईटी केवल शिक्षण संस्थान नहीं, स्वतंत्र भारत की सबसे सफल वैश्विक पहचान में से एक हैं। क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में आईआईटी बांबे दुनिया में 129वें और भारत में दूसरे स्थान पर रहा। दशकों की मेहनत से अर्जित इस प्रतिष्ठा की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन प्रतिष्ठा की रक्षा सवालों को दबाने से नहीं, बल्कि कठिन सवालों का ईमानदारी से सामना करने से होती है। साहिल की मृत्यु से पहले की घटनाओं को लेकर दो अलग पक्ष सामने आए हैं। एक ओर परीक्षा के दौरान फोन के इस्तेमाल की बात है और परिवार के जातिगत भेदभाव के आरोप हैं और दूसरी ओर आईआईटी बांबे का कहना है कि छात्र ने प्रशासन को कोई शिकायत नहीं दी थी। शिक्षक समुदाय का तर्क है कि परीक्षा निरीक्षक ने केवल संस्थान की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज किया है, पर अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए किसी एक सुविधाजनक कहानी को अंतिम सत्य मान लेना गलत होगा। जातिगत भेदभाव भारत की सामाजिक वास्तविकता है और यह मान लेना भोलापन होगा कि प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वार पर पहुंचते ही जाति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भेदभाव हमेशा खुले लिखित आदेश के रूप में सामने नहीं आता। वह उपहास और कमतर समझे जाने के रूप में भी दिखाई दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण विरोधी सोच, जातिगत मजाक, सूक्ष्म आक्रामक व्यवहार और असमान शैक्षणिक सहयोग जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। वास्तविक शिकायतों को राजनीति बताकर खारिज करना पीड़ित छात्रों का भरोसा तोड़ेगा और उन्हें शिकायत करने से रोकेगा, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई छात्र सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से आता है, इसलिए परीक्षा अनुशासन से मुक्त नहीं हो सकता। नकल के आरोप की जांच करना शिक्षक का कर्तव्य है। यदि जांच में पाया जाता है कि संबंधित शिक्षक ने नियमानुसार काम किया और जातिगत अपमान नहीं किया तो उनकी प्रतिष्ठा बहाल की जानी चाहिए।

शिक्षा का उद्देश्य केवल सफल विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि गलती करने वाले छात्र को संभलना और फिर खड़ा होना भी सिखाना है। नियम कठोर हो सकते हैं, व्यवहार अपमानजनक नहीं। अनुशासन जरूरी है, पर उसके साथ सुनवाई, स्पष्ट प्रक्रिया, परामर्श और भावनात्मक सहारा भी जरूरी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2020-21 से 2024-25 के बीच आईआईटी में 53 छात्रों की मौत हुई, जिनमें 45 आत्महत्याएं थीं। मृतकों में 29 छात्र एससी-एसटी अथवा ओबीसी समुदायों से थे। ये आंकड़े जातिगत कारण को न तो सिद्ध करते हैं, न खारिज। छात्रों की आत्महत्या प्रायः किसी एक घटना का परिणाम नहीं होती। शैक्षणिक दबाव, अकेलापन, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक चिंता, पारिवारिक अपेक्षाएं, सामाजिक भेदभाव आदि कई कारण एक साथ काम कर सकते हैं। इसीलिए संस्थागत सुधार अब विकल्प नहीं, आवश्यकता हैं।

एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम पर भी संतुलित दृष्टि चाहिए। जातिगत अपमान और अत्याचार से सुरक्षा देने वाला यह कानून आवश्यक है। इसके कमजोर होने का सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होगा, जिनके पास पहले ही शक्ति और संसाधन कम हैं। साथ ही, यदि निष्पक्ष जांच या न्यायिक प्रक्रिया से किसी शिकायत का दुर्भावनापूर्ण, झूठा अथवा निजी बदले के लिए किया गया इस्तेमाल सिद्ध होता है तो उसे भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। कानून की रक्षा और उसके दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल पर रोक, ये विरोधी नहीं, पूरक लक्ष्य हैं। झूठा मुकदमा वास्तविक पीड़ितों की लड़ाई को भी कमजोर करता है। आईआईटी बांबे की शुरुआती सार्वजनिक टिप्पणी और उसके बाद आई क्षमायाचना यह याद दिलाती है कि ऐसी त्रासदी के बाद संस्थानों को जल्दबाजी में कारण निर्धारित नहीं करना चाहिए। प्रशासन को सत्यापित तथ्यों तक सीमित रहना चाहिए, परिवार की निजता की रक्षा करनी चाहिए और जांच को प्रभावित करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। यही संयम मीडिया, राजनीतिक दलों, छात्र समूहों और शिक्षक संगठनों को भी दिखाना होगा। मार्च और प्रतिमार्च से न्याय नहीं निकलता। निष्पक्ष जांच, दस्तावेजी साक्ष्य और संस्थागत सुधार से निकलता है। देश को अपने आईआईटी से दो बातों की मांग एक साथ करनी चाहिए- विश्वस्तरीय उत्कृष्टता और मानवीय संवेदना। शैक्षणिक मानकों से कोई समझौता न हो, नकल को कोई संरक्षण न मिले और राजनीतिक दबाव में नियम न बदलें, लेकिन वास्तविक जातिगत भेदभाव को भी नकारा न जाए और हर शिकायत की सुनवाई स्वतंत्र, विश्वसनीय और समयबद्ध संस्थागत ढांचे में हो। दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई हो और आरोप असत्य या दुर्भावनापूर्ण सिद्ध होने पर निर्दोष व्यक्ति का सम्मान लौटाया जाए। आईआईटी की प्रतिष्ठा तब और मजबूत होगी, जब परिसर का हर छात्र यह भरोसा कर सके कि यहां नियम सबके लिए समान हैं, भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं और जीवन किसी एक गलती से कहीं अधिक मूल्यवान है।

अभियान

पितरों के प्रति कृतज्ञता का समय, पूर्णिमा श्राद्ध से शुरू हुआ पितृपक्ष

भारतीय सनातन परंपरा में पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं माना जाता, बल्कि यह अपने पूर्वजों के प्रति स्मरण, श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है। परिवार की जिन पीढ़ियों ने जीवन, संस्कार, परंपराएं और अनुभव अगली पीढ़ी तक पहुंचाए, पितृपक्ष में उन्हीं पूर्वजों को याद कर उनके निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। वर्ष 2026 में पितृपक्ष का आरंभ 26 सितंबर, शनिवार से हो रहा है। इस दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से जुड़े श्राद्ध का विशेष महत्व रहेगा।

ज्योतिषाचार्य पंडित ज्योतिषविद् आचार्य सुनील किमोथी के अनुसार, पितृपक्ष की शुरुआत को लेकर तिथियों को ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि भाद्रपद पूर्णिमा तिथि 25 सितंबर की रात 11 बजकर 09 मिनट से प्रारंभ होगी और 26 सितंबर की रात 10 बजकर 18 मिनट तक रहेगी। 25 सितंबर को चंद्रमा का उदय शाम 5 बजकर 27 मिनट पर चतुर्दशी तिथि में होगा। इसके बाद पूर्णिमा तिथि का प्रभाव 26 सितंबर को रहेगा। इसी कारण पूर्णिमा की उदयातिथि 26 सितंबर मानी जाएगी। पितृपक्ष में पूर्णिमा तिथि पर उन पूर्वजों का श्राद्ध करने की परंपरा है, जिनका निधन पूर्णिमा तिथि को हुआ हो। इसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पितृपक्ष के नियमित श्राद्ध शुरू होते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध को एक ही नहीं माना जाता। दोनों का अपना अलग तिथि-विधान है। इसलिए जिन परिवारों में पूर्वज की मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई है, उनके लिए पूर्णिमा श्राद्ध का विशेष महत्व हो जाता है।

पितृपक्ष के दिनों में घर का वातावरण शांत और सात्विक रखने की परंपरा रही है। मान्यता है कि इन दिनों व्यक्ति को बाहरी दिखावे के बजाय आत्मचिंतन, संयम और पूर्वजों के स्मरण पर ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध का मूल भाव श्रद्धा से जुड़ा है और इसी कारण इसे केवल कर्मकांड के रूप में देखने के बजाय परिवार की परंपरा और पूर्वजों के प्रति सम्मान के रूप में भी समझा जाता है।

घर में पहली बार श्राद्ध करने वाले लोगों के लिए कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। श्राद्ध वाले दिन सबसे पहले घर की साफ-सफाई की जानी चाहिए। जिस स्थान पर श्राद्ध, तर्पण या पितरों का स्मरण किया जाना हो, उसे भी स्वच्छ रखा जाता है। पूजा या धार्मिक कार्य के दौरान मन को शांत रखने का प्रयास किया जाता है। परिवार के सदस्यों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अनावश्यक विवाद, क्रोध और अशांति से बचें।

परंपरा में श्राद्ध के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून काटने से बचने की बात भी कही गई है। इसका संबंध बाहरी सजावट से अधिक उस भाव से माना जाता है, जिसमें व्यक्ति पितरों के प्रति समर्पित होकर सादगी और संयम के साथ दिन व्यतीत करता है। अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में श्राद्ध से जुड़े नियमों में कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए अपने कुल की परंपरा और स्थानीय आचार-विधान के अनुसार कर्म करना उचित माना जाता है।

पितृपक्ष में तर्पण का भी विशेष स्थान है। जल अर्पित करते समय व्यक्ति अपने पूर्वजों को स्मरण करता है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। भारतीय परंपरा में जल को जीवन का आधार माना गया है, इसलिए तर्पण के माध्यम से पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। इसी प्रकार श्राद्ध में अन्न और अन्य सामग्री का अर्पण भी पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है।

श्राद्ध की परंपरा के पीछे एक महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष भी दिखाई देता है। पितृपक्ष परिवार को अपनी पिछली पीढ़ियों से जोड़ने का अवसर देता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में परिवार की नई पीढ़ी कई बार अपने पूर्वजों के जीवन, संघर्ष और योगदान से अनजान रह जाती है। ऐसे में पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार की स्मृतियों को जीवित रखने का माध्यम भी बन सकता है। बच्चों को अपने दादा-दादी, नाना-नानी और उनसे पहले की पीढ़ियों के बारे में बताना भी इस अवसर को अर्थपूर्ण बना सकता है।

पूर्वजों का स्मरण केवल उनके नाम लेने तक सीमित नहीं है। उनके जीवन से मिली सीख, संस्कार और परिवार के प्रति उनके योगदान को याद करना भी पितृस्मरण का हिस्सा माना जा सकता है। किसी परिवार में पूर्वजों ने कठिन परिस्थितियों में घर संभाला होगा, किसी ने शिक्षा के लिए संघर्ष किया होगा, किसी ने जमीन-जायदाद या व्यवसाय खड़ा किया होगा और किसी ने परिवार को विपरीत समय में एकजुट रखा होगा। पितृपक्ष ऐसे योगदानों को याद करने का अवसर देता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। हालांकि इस तरह की मान्यताएं आस्था और परंपरा पर आधारित हैं। इनके पीछे मुख्य भावना पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की है। इसी भावना के कारण श्राद्ध को परिवार के संस्कारों से जोड़कर देखा जाता है।

पितृपक्ष का महत्व इस बात में भी है कि यह व्यक्ति को अपने जीवन और परिवार के संबंधों पर विचार करने का अवसर देता है। हम जिस घर, परिवार, सामाजिक पहचान और जीवन व्यवस्था का हिस्सा हैं, उसके पीछे कई पीढ़ियों का योगदान रहा है। वर्तमान पीढ़ी को यह याद दिलाने वाला पर्व है कि जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है। हमारे अस्तित्व में अतीत की अनेक पीढ़ियों की मेहनत, संस्कार और अनुभव जुड़े हुए हैं।

26 सितंबर से शुरू होने वाला यह पक्ष इसी भाव को आगे बढ़ाएगा। पहले पूर्णिमा तिथि से जुड़े श्राद्ध का विधान होगा और उसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से नियमित श्राद्ध क्रम आगे बढ़ेगा। पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा, जिसे उन पितरों के स्मरण का विशेष अवसर माना जाता है जिनकी श्राद्ध तिथि किसी कारण से ज्ञात न हो या जिनका तिथि-विशेष श्राद्ध नहीं किया जा सका हो।

श्राद्ध के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात विधि से अधिक भावना को माना गया है। पूर्वजों को याद करते समय मन में सम्मान, कृतज्ञता और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। पितृपक्ष हमें यह भी सिखाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसी विरासत छोड़कर जाएंगे। जिस प्रकार हम अपने पूर्वजों को उनके कर्मों और संस्कारों के लिए याद करते हैं, उसी प्रकार भविष्य की पीढ़ियां भी हमें हमारे कार्यों से याद करेंगी।

इसलिए पितृपक्ष का संदेश केवल अतीत की ओर देखने का नहीं, बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाने का भी है। अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करना, परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाना इस परंपरा की भावना को सार्थक बना सकता है। 26 सितंबर से शुरू हो रहा पितृपक्ष इसी स्मृति, श्रद्धा और कृतज्ञता का अवसर लेकर आएगा, जिसमें परिवार अपने पूर्वजों को नमन करते हुए उनके प्रति अपने दायित्व और संबंध को फिर से महसूस करेगा।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

विश्व पर्यटन दिवस पर गिफ्ट सिटी में 'गुजरात पर्यटन वर्ष' समारोह

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के करकमलों से 'गुजरात पर्यटन वर्ष' का लोगो तथा 'गुजरात फिल्म शूटिंग परमिशन पोर्टल' लॉन्च

- पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. जयराम गामित की प्रेरक उपस्थिति
- गांधीनगर में 'हायरॉक्स' तथा अहमदाबाद में 'आयरनमैन/हाफ-आयरनमैन' जैसी वैश्विक फिटनेस प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी
- उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी का पर्यटन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 'सामूहिक भागीदारी' के साथ 'स्वच्छता', 'स्वास्थ्य' और 'सॉफ्ट स्पोकन स्किल' के त्रि-सूत्रीय मंत्र पर बल देने का अनुरोध
- राज्य के टूरिज्म इकोसिस्टम को और सुदृढ़ बनाने के लिए स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र में 8 एमओयू हुए
- उत्कृष्ट कार्य करने वाले होमस्टे संचालकों एवं गाइड्स को 'टूरिज्म चैम्पियन्स' के रूप में सम्मानित किया गया
- राज्य के 100 चयनित गाँवों में होमस्टे सुविधाओं को प्रोत्साहित कर विकसित किया जाएगा
- राज्य के सांस्कृतिक उत्सवों में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टूर ऑपरेटर्स को गैप फंडिंग देने के लिए राज्य सरकार तत्पर
- राज्य में और 1,000 टूरिस्ट गाइड्स को प्रशिक्षित किया जाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे

गांधीनगर : गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 को 'गुजरात पर्यटन वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रविवार को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में "विश्व पर्यटन दिवस" मनाया गया। गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (टीसीजीएल) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. जयरामभाई गामित उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के करकमलों से 'गुजरात पर्यटन वर्ष' का आधिकारिक लोगो जारी किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को श्रेष्ठ सुविधाएँ तथा यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी भागीदारों को सामूहिक भागीदारी के साथ कार्य करना होगा। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूर ऑपरेटर्स तथा टैक्सी-रिक्शा ड्राइवर्स सहित सभी स्टेकहोल्डर्स यदि 'स्वच्छता', 'स्वास्थ्य' और 'सॉफ्ट स्पोकन स्किल'; इन तीन बातों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करेंगे, तो गुजरात का पर्यटन क्षेत्र बुलेट ट्रेन से भी अधिक तेजी से प्रगति करेगा और सरकार इस दिशा में पूरा सहयोग प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि सोमनाथ, अंबाजी, पावागढ और द्वारका जैसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर हो रहे विकास कार्यों के साथ स्थानीय स्तर पर स्वच्छता एवं नागरिक कर्तव्यों का पालन एक सामाजिक क्रांति के समान है। उन्होंने जोड़ा कि प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम या त्योहार को पर्यटन के साथ जोड़ा जाए।

कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने वैश्विक खेल तथा पर्यटन को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही स्पोर्ट्स इवेंट 'हायरॉक्स' का आयोजन आगामी 26 से 28 नवंबर के दौरान गांधीनगर में होगा। इसमें 1,000 से अधिक विदेशी एथलीट्स सहित कुल लगभग 10,000 पर्यटकों के भाग लेने की संभावना है। इस इवेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए शाम के समय पर्यटन निगम द्वारा विशेष 'भजन क्लबिंग' का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार, आगामी 14 फरवरी को अहमदाबाद में आयरनमैन/हाफ-आयरनमैन इवेंट का आयोजन किया जाएगा, जो गुजरात के स्पोर्ट्स टूरिज्म को वैश्विक मानचित्र पर नया स्थान दिलाएगा।

श्री संघवी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए अंबाजी, सोमनाथ, द्वारका और पावागढ जैसे धार्मिक स्थलों का आधुनिक विकास किया जा रहा है। नई होमस्टे नीति अंतर्गत 100 चयनित गाँवों में पारंपरिक शैली को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त होमस्टे विकसित किए जाएंगे और कवांट की होली, उत्तरायण एवं नवरात्रि जैसे उत्सवों तथा धरोई वाटर रिजर्वायर व शिवराजपुर जैसे इको-टूरिज्म स्थलों पर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टूर ऑपरेटर्स को गैप फंडिंग देने की दिशा में भी राज्य सरकार प्रस्तुतियों के आधार पर सकारात्मक सहयोग प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियाँ, प्रशिक्षण और गैप फंडिंग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। उप मुख्यमंत्री ने राज्य के टूर ऑपरेटर्स से केवल सरकार पर निर्भर रहने के बजाय नवरात्रि, पतंग उत्सव और छोटाउदेपुर की कवांट की होली जैसे अनूठे सांस्कृतिक उत्सवों के लिए आकर्षक टूर पैकेज तैयार कर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की अपील की। उन्होंने जोड़ा कि इसके अलावा ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे कल्चर तथा हाइजीनिक व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति में सुधार करने तथा 1,000 से अधिक नए टूर गाइड्स तैयार करने सहित स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया गया है।

इस अवसर पर राज्य में सिनेमैटिक टूरिज्म तथा डेस्टिनेशन प्रमोशन को वेग देने के लिए उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के करकमलों से 'गुजरात फिल्म शूटिंग परमिशन पोर्टल' का अनावरण किया गया। इस सिंगल विंडो डिजिटल पोर्टल के माध्यम से फिल्म शूटिंग के लिए विभिन्न अनुमतियाँ एवं एनओसी सरल, तेज और पारदर्शी बनेंगी।

इसके अलावा इस अवसर पर पर्यटन इकोसिस्टम को और सुदृढ़ बनाने के लिए स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा क्षेत्र में 08 एमओयू संपन्न किए गए। इनमें गुजरात पर्यटन निगम द्वारा 'हायरॉक्स/आयरनमैन' के साथ स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए, 'बुक माई शो' के साथ डिजिटल टिकटिंग के लिए तथा कच्छ यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, एसवीएनआईटी, कौशल-द स्किल यूनिवर्सिटी, टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव्स ट्रस्ट (टाटा स्ट्राइव) और ईडीआईआई के साथ कौशल विकास के लिए भागीदारी शामिल हैं।

इस कार्यक्रम के दौरान गिर सोमनाथ के होमस्टे संचालक श्री पार्थ हडिया और कच्छ के टूरिस्ट गाइड श्री केतन गिरी गोस्वामी जैसे स्थानीय स्टेकहोल्डर्स ने अपनी सफलता की गाथाएँ प्रस्तुत कीं। साथ ही, राज्य के कुछ होमस्टे संचालकों और टूर गाइड्स को 'टूरिज्म चैम्पियन्स' के रूप में सम्मानित किया गया।

इस समारोह में 'हॉस्पिटैलिटी, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन (एमआईसीई) और इन्वेस्टमेंट' विषय पर उच्च स्तरीय पैनल चर्चा आयोजित हुई तथा राज्य के कारीगरों द्वारा मीनाकारी, काष्ठकला और अकीक पत्थर की कारीगरी का जीवंत प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में पर्यटन सचिव डॉ. कुलदीप आर्य द्वारा समग्र कार्यक्रम की विस्तृत भूमिका प्रस्तुत करते हुए सभी का स्वागत किया गया।

इस कार्यक्रम में गुजरात पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. विपिन गर्ग, गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड के सदस्य सचिव श्री रमेश मेरजा सहित वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के अग्रणी सहित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े नागरिक, होटलियर्स तथा टूर ऑपरेटर्स उपस्थित रहे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से साबरमती (काळी गाम) में 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक WAG-12 लोकोमोटिव शेड का लोकार्पण

गांधीनगर, 27 सितंबर : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत साबरमती (काळी गाम) में 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए अत्याधुनिक WAG-12 रखरखाव शेड का रविवार को भव्य लोकार्पण किया गया।

साबरमती लोकोमोटिव शेड की प्रमुख विशेषताएँ और लाभ

उच्च क्षमता वाले इंजन : इस शेड में होमिंग एवं रखरखाव किए जाने वाले WAG-12 लोकोमोटिव की लगभग 12,000 हॉर्स पावर (HP) की प्रचंड क्षमता है, जो भारी एवं लंबी मालगाड़ियों के तेज तथा सुचारु संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धत होंगे।

रखरखाव अनुबंध (एमएसए) : कुल 300 WAG-12 लोकोमोटिव के वैज्ञानिक रखरखाव के लिए 'मैसर्स मधेपुरा लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (एमईएलपीएल)' और साबरमती लोकोमोटिव शेड के बीच मैंटेनेंस सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) किया गया है।

चरणबद्ध उपलब्धता : वर्तमान में 154 WAG-12 लोकोमोटिव की होमिंग पूर्ण हो चुकी है, जबकि वर्ष 2027-28 तक सभी 300 लोकोमोटिव प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यक्षमता में वृद्धि : अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं तथा वैज्ञानिक निगरानी के कारण लोकोमोटिव की उपलब्धता, विश्वसनीयता और रेलवे की समग्र मालवहन क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी।

इस अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से भारतीय रेलवे की मालवहन क्षमता एवं परिचालन कार्यक्षमता के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू होगा।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (इंजन नंबर 6059) को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया।

यहाँ उल्लेखनीय है कि आज के आधुनिक युग में रेलवे केवल परिवहन का माध्यम न रहते हुए 'आत्मनिर्भर भारत' एवं 'मेक इन इंडिया' की संकल्पना को साकार करने वाले सुशासन तथा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गई है।

कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला रेलवे नेटवर्क देश के विभिन्न राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों को एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह सहित महानुभावों ने शेड के विकास की गति को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का निरीक्षण किया।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, डीआरएम श्री वेद प्रकाश, महापौर श्री हितेशभाई बारोट, सचेतक श्री अतुल मिश्रा, विधायक श्री हर्षद पटेल, अग्रणी श्री प्रेरक शाह सहित रेलवे के अनेक वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी तथा प्रबुद्ध नागरिक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

महंगाई का कहर: दैनिक दरों में मामूली वृद्धि और सरकारी नीतियों ने मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक संकट पैदा कर दिया है

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

भारत में महंगाई जिस तरह से बेतहाशा बढ़ रही है, उसमें दो, पांच या सात रुपये की बढ़ोतरी मामूली सी लगती है, लेकिन रोजमर्रा की चीजों की कुल कीमत चौंका देने वाली है। क्योंकि हम कहते हैं कि सिर्फ पांच रुपये बढ़े हैं, है ना? दो रुपये में क्या फर्क पड़ता है? यह दैनिक बढ़ोतरी एक कप चाय के बराबर है।

जब सरकारी दलों के प्रवक्ता, टीवी स्टूडियो के आर्थिक विश्लेषक और कॉरपोरेट जगत के नीति निर्माता हमें अपने तर्क देते हैं, तो वे आम भारतीय परिवार की वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, घर से लेकर दफ्तर तक

और बच्चों की शिक्षा तक, आज आम आदमी के जीवन का लगभग हर पहलू महंगाई की चपेट में है। किसी वस्तु की कीमत में मामूली वृद्धि पहली नजर में बहुत कम लगती है और इसे सामान्य वृद्धि समझकर आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है।

लेकिन सवाल यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीजें सस्ती हो जाती हैं, तो इसका लाभ आम नागरिक को क्यों नहीं मिलता? जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तो सरकार कीमत कम करने के बजाय उस पर शुल्क बढ़ा देती है; जब कच्चा तेल महंगा हो जाता है, तो इसे तुरंत वैश्विक संकट का नाम देकर जनता पर थोप दिया जाता है। अंततः, आम आदमी इस अन्यायपूर्ण नीति का शिकार बन जाता है।

इस प्रकार, सरकार की कमजोर नीतियों और लापरवाह उपायों के कारण देश का मध्यम वर्ग दबाव में है। मध्यम वर्ग न तो गरीब है और न ही अति-अमीर, इसलिए वे अपनी आय को परामर्श या कंपनी के खर्चों या टैक्स हेवन में छिपा नहीं सकते। दूसरी ओर, उनका वेतन निश्चित है, आय का स्रोत एक ही है, और नौकरी छूटने पर मध्यम वर्ग के परिवारों को लगातार बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए तंग बजट पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर, वास्तविक मुद्रास्फीति दर आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है, लगभग 10% से 12%। परिणामस्वरूप, वेतनभोगी वर्ग की वास्तविक आय में वृद्धि होने के बजाय हर साल कमी आ रही है। जो जीवन स्तर कल 30,000 रुपये पर बना हुआ था, आज उसे बनाए रखने के लिए 38,000 रुपये की आवश्यकता है। जब आय में वृद्धि नहीं होती, तो परिवार खर्च में कटौती करते हैं। इस प्रकार, जिसे आर्थिक विशेषज्ञ मुद्रास्फीति कहते हैं, वह मध्यम वर्ग के लिए एक "आर्थिक संकट" है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में आयोजित अशोकजी सिंघल जन्म शताब्दी संगोष्ठी में सहभागी हुए

गांधीनगर : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को अहमदाबाद में आयोजित 'अशोकजी सिंघल जन्म शताब्दी संगोष्ठी' में उपस्थित रहकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि अशोकजी सिंघल एक तपस्वी राष्ट्रसाधक तथा सांस्कृतिक चेतना के संवाहक थे। उनका समग्र जीवन देश, आध्यात्मिक परंपरा और सनातन संस्कृति के संरक्षण तथा राष्ट्रजीवन में जागृति के लिए समर्पित रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि करोड़ों हिन्दुओं की आस्था के केन्द्र अयोध्या में भव्य-दिव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए अशोकजी सिंघल द्वारा किया गया संघर्ष एवं संकल्प आज साकार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तथा प्राण-प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अवसर अशोकजी सिंघल सहित अनेक राष्ट्रसाधकों के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने वाला बना है।

पटेल ने जोड़ा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण के साथ विकास को भी नई गति मिली है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, अंबाजी कॉरिडोर सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 'विरासत भी, विकास भी' का संकल्प साकार हो रहा है। देश की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को विश्व के समक्ष उजागर करने का कार्य हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अशोकजी सिंघल ने हिन्दू समाज की एकता के लिए विशाल हिन्दू सम्मेलनों का आयोजन कर वेद, संस्कृत, गौ, गंगा, तीर्थ, तीर्थपुरोहित, धर्माचार्यों तथा मठ-मंदिरों की प्राचीन परंपरा की पुनर्स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचारों एवं कार्यों ने अनेक युवाओं के अंतर्मन में देशप्रेम तथा राष्ट्रभावना की ज्योति प्रज्वलित की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन की 25 वर्षों की सेवायात्रा के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सेवा संकल्प अभियान' के माध्यम से सेवा, सुशासन और राष्ट्रप्रथम की भावना को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास हो रहा है। अशोकजी सिंघल के जीवन से आगामी पीढ़ी को राष्ट्रप्रथम, संकल्पनिष्ठा, साधना और समर्पण का संदेश ग्रहण करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के साथ आधुनिक एवं विकसित भारत के निर्माण में भी सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अशोकजी सिंघल के विचारों तथा जीवनकार्य को नई पीढ़ी तक पहुँचाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।

मुख्यमंत्री ने अशोकजी सिंघल की राष्ट्रसेवा एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा को नमन करते हुए 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के जयघोष के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संतों-महंतों तथा विश्व हिन्दू परिषद के अग्रणियों के साथ अशोकजी सिंघल के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी देखी।

कार्यक्रम में विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेन्द्र जैन, पूज्य संत-महंत सर्व पुरुषोत्तम शास्त्रीजी, धर्मनंदन कोठारी महाराज, भगवंतदासजी, मोहनदासजी, सतनामसिंह, डॉ. खुशरू होमी घडियाली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सहकार्यवाह सुनील बोरिसा, मगनभाई पटेल, विश्व हिन्दू परिषद-गुजरात के महासचिव अश्विनभाई पटेल, अध्यक्ष हर्षदभाई गिलिटवाला, कर्णावती महानगर के अध्यक्ष अंकुरभाई सहित संत, महानुभाव और आमंत्रित लोग उपस्थित रहे।

गुजरात में नींबू की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल: 400 रुपये प्रति किलो की कीमत पर, ये मिठाइयों से भी महंगे हो गए हैं

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

गुजरात में जब गर्मी शुरू हो रही है, वातावरण गर्म हो रहा है, तब गर्मी में भी ठंडक का एहसास देने वाला नींबू पानी उपभोक्ताओं के दांतों को और भी खट्टा कर रहा है। क्योंकि नींबू की कीमत इतनी बढ़ गई है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। 300 से 400 रुपये प्रति किलो, यानी कीमत मिठाई के बराबर हो गई है। यहां तक कि सेब जैसे महंगे फल भी आधी कीमत पर बिक रहे हैं।

जहां गरीब परिवार नींबू के बारे में भूल चुके हैं, वहीं मध्यम वर्ग के लोग भी नींबू की बढ़ती कीमतों को वहन नहीं कर सकते। आमतौर पर नींबू की कीमतें अप्रैल-मई के महीनों में बढ़ जाती हैं। गर्मियों में नींबू की मांग बढ़ने पर कीमतों में वृद्धि होना स्वाभाविक है, लेकिन इस बार कीमतें सितंबर से ही बढ़ रही हैं, जो एक बड़ा सवालिया निशान है।

एक महीने पहले, आँगन में 20 किलो नींबू का भाव 1,000 से 1,500 रुपये था, जो अब बढ़कर 2,000 से 4,000 रुपये प्रति 20 किलो हो गया है। यह एक ऐतिहासिक स्तर है। अब खुदरा बाजार में एक किलो नींबू का भाव 250 से 300 रुपये तक हो गया है। नींबू की कीमत में वृद्धि का कारण गर्मी के कारण बढ़ी मांग है। दूसरी ओर, नींबू की फसल न के बराबर है। एक महीने पहले, आँगन में प्रतिदिन 1.5 लाख किलो नींबू की कटाई हो रही थी, जबकि अब केवल 40 हजार किलो ही प्राप्त हो रहे हैं। मांग प्राप्त फसल से चार गुना अधिक है। बहुत कम वर्षा के कारण फसल को नुकसान हुआ है। जल्दी पकने वाली नकदी फसलों और अनियमित वर्षा के कारण सब्जियों के खराब होने से उनका उत्पादन कम हो गया है और सब्जियां महंगी हो गई हैं। कम वर्षा के कारण पेड़ों पर लगे नींबू खराब होने लगे हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से अहमदाबाद में एसजेडवीएस बिजनेस एक्सपो-2026 का भव्य उद्घाटन

गांधीनगर : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से रविवार को अहमदाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में झालावाड वीशा माली स्थानकवासी (एसजेडवीएस) जैन समाज द्वारा आयोजित एसजेडवीएस बिजनेस एक्सपो-2026 का उद्घाटन किया गया।

समाज के सदस्यों के उत्थान तथा प्रगति के साथ सरकार की विभिन्न विकासोन्मुखी पहलों का लाभ समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और समाज सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़े; इस आशय से इस एक्सपो का आयोजन किया गया है।

इस बिजनेस एक्सपो में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोवाइडर, इंडस्ट्रियल, बिल्डिंग मटेरियल्स, ज्वेलरी, इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, फैशन डिजाइनर, खान-पान के स्टॉल सहित विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 80 स्टॉल लगाए गए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विभिन्न स्टॉलों पर जाकर उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

इस एक्सपो का आयोजन समाज के अध्यक्ष अपूर्व संघवी, उपाध्यक्ष अजय दोशी, सचिव दर्शन संघवी, सह-सचिव अल्पेश धोळकिया, कोषाध्यक्ष भाविक वसाणी तथा सह-कोषाध्यक्ष विवेक शाह सहित टीम के मार्गदर्शन में किया गया है।

इस अवसर पर समिति के सदस्य सर्व हितेश संघवी, भावेश हकाणी, निलय शाह, चैतन्य संघवी, ऋषभ संघवी, हार्दिक गोपाणी, हितेन संघवी, विशाल संघवी और अंकित शाह सहित समाज के अग्रणी, उद्योगपति और व्यापारी उपस्थित रहे।

दो अक्टूबर को मोबाइल दुकानों पर नहीं चलेगा यूपीआई, 'नो यूपीआई डे' का ऐलान

नई दिल्ली। देशभर के मोबाइल फोन रिटेलर्स ने आगामी दो अक्टूबर को 'नो यूपीआई डे' मनाने का फैसला किया है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (एआईएमआरए) ने यह निर्णय व्यापारिक यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के विरोध में लिया है। संगठन के आह्वान पर गांधी जयंती के दिन बड़ी संख्या में मोबाइल दुकानदार यूपीआई से भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। इस दौरान दुकानों पर लगे यूपीआई क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढककर रखा जाएगा। रिटेलर्स का कहना है कि प्रतीकात्मक रूप से किया जा रहा यह विरोध सरकार और संबंधित एजेंसियों तक उनकी आर्थिक चिंताओं को पहुंचाने का माध्यम होगा।

एआईएमआरए के अनुसार, 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के पात्र व्यापारिक यूपीआई लेनदेन पर 0.4 फीसदी एमडीआर लागू किए जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। संगठन का कहना है कि इस शुल्क का सीधा असर उन छोटे और मध्यम दुकानदारों पर पड़ सकता है, जिनके कारोबार में डिजिटल भुगतान का हिस्सा लगातार बढ़ा है। मोबाइल फोन की बिक्री में बड़ी राशि के लेनदेन आम हैं और ऐसे में प्रत्येक भुगतान पर शुल्क लगने से व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है। रिटेलर्स का तर्क है कि पहले से सीमित मार्जिन पर काम करने वाले छोटे कारोबारियों के लिए अतिरिक्त शुल्क उनकी कमाई को प्रभावित कर सकता है।

संगठन ने स्पष्ट किया है कि उसका विरोध यूपीआई, डिजिटल भुगतान या डिजिटल इंडिया की अवधारणा के खिलाफ नहीं है। एआईएमआरए का कहना है कि मोबाइल रिटेलर्स लंबे समय से डिजिटल भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ग्राहकों के लिए यूपीआई को सुविधाजनक भुगतान माध्यम मानते हैं। उनकी मुख्य मांग व्यापारिक यूपीआई लेनदेन पर शून्य एमडीआर व्यवस्था को जारी रखने की है। संगठन का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों को उस पर अतिरिक्त आर्थिक भार से मुक्त रखना जरूरी है।

एआईएमआरए ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजी गई अपनी गुजारिश में भी इस मुद्दे को उठाया है। संगठन ने सरकार से प्रस्तावित एमडीआर व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। रिटेलर्स का कहना है कि मोबाइल कारोबार में प्रतिस्पर्धा पहले से काफी अधिक है और दुकानदारों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमत, सेवा और अन्य खर्चों के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। ऐसे में भुगतान पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क व्यापार की लागत को प्रभावित कर सकता है।

एआईएमआरए के उपाध्यक्ष और दिल्ली-एनसीआर अध्यक्ष तरविंदर सिंह ने कहा कि रिटेलर्स का उद्देश्य डिजिटल भुगतान व्यवस्था को रोकना नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यापारी यूपीआई और डिजिटल इंडिया के समर्थक हैं, लेकिन उनका आग्रह है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर व्यापारियों से एमडीआर नहीं लिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, छोटे दुकानदारों के लिए जीरो एमडीआर व्यवस्था जारी रहने से डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल भी बढ़ेगा और कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं आएगा।

'नो यूपीआई डे' के लिए दुकानदारों से दो अक्टूबर को अपने प्रतिष्ठानों पर यूपीआई क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढकने की अपील की गई है। इस दौरान ग्राहकों से नकद अथवा उपलब्ध अन्य भुगतान विकल्पों का इस्तेमाल करने को कहा जा सकता है। संगठन का मानना है कि गांधी जयंती के दिन सामूहिक रूप से किया जाने वाला यह सांकेतिक विरोध सरकार का ध्यान रिटेल कारोबारियों की मांग की ओर आकर्षित करेगा।

एमडीआर को लेकर व्यापारिक संगठनों और डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जुड़े पक्षों के बीच चर्चा का केंद्र यह है कि डिजिटल भुगतान का खर्च किस प्रकार वहन किया जाए। व्यापारियों का कहना है कि यूपीआई के विस्तार ने भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाया है और ग्राहकों तथा दुकानदारों दोनों के लिए लेनदेन में सुविधा बढ़ी है। ऐसे में शुल्क की नई व्यवस्था लागू होने पर छोटे कारोबारियों की लागत और उनके मुनाफे पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

रिटेलर्स के मुताबिक, मोबाइल फोन की बिक्री के अलावा मोबाइल एक्सेसरीज, रिपेयरिंग और अन्य संबंधित कारोबार से जुड़े छोटे दुकानदार भी डिजिटल भुगतान पर निर्भर हैं। ग्राहकों की ओर से यूपीआई को प्राथमिकता दिए जाने के कारण दुकानदारों ने भी क्यूआर कोड भुगतान को अपने कारोबार का नियमित हिस्सा बना लिया है। संगठन का कहना है कि यदि व्यापारिक भुगतान पर शुल्क लागू होता है तो इसका असर केवल बड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले दुकानदार भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।

एआईएमआरए ने सरकार से आग्रह किया है कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की नीति के साथ व्यापारियों की लागत का भी ध्यान रखा जाए। संगठन का कहना है कि मोबाइल रिटेल सेक्टर में बड़ी संख्या में छोटे कारोबारी काम करते हैं और उनकी आय का बड़ा हिस्सा सीमित मार्जिन वाले कारोबार पर निर्भर करता है। ऐसे में भुगतान प्रणाली से जुड़ा अतिरिक्त खर्च उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दो अक्टूबर को होने वाला 'नो यूपीआई डे' इसी मांग को लेकर रिटेलर्स की ओर से प्रस्तावित सामूहिक विरोध का हिस्सा है। क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढकना इस विरोध का प्रतीक होगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रिटेलर्स की इस पहल के बाद सरकार और संबंधित संस्थाओं की ओर से एमडीआर को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल मोबाइल रिटेलर्स ने साफ कर दिया है कि वे प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो अक्टूबर को यूपीआई भुगतान से दूरी बनाकर अपनी मांग को प्रमुखता से उठाएंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के करकमलों से देश की पहली एलएनजी संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराए जाने के अलावा 1,542 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया गया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के करकमलों से देश की पहली एलएनजी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराए जाने के अलावा साबरमती अत्याधुनिक WAG-12 लोकोमोटिव मैंटेनेंस शेड तथा साबरमती–कलोल–भांडू मोटीदाऊ एवं साबरमती–साणंद–जखवाडा रेलखंड पर एबीएस प्रणाली और अहमदाबाद मंडल के 404 किलोमीटर लंबे रेलखंड (अहमदाबाद से पालनपुर तथा सामखियाळी) पर 'कवच' प्रणाली तथा साबरमती–सरखेज रेलवे लाइन के डबलिंग कार्य का शिलान्यास किया गया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह

- साबरमती स्टेशन का कोई विश्वास न कर सके; ऐसा कायाकल्प हुआ है
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को रेलवे ने चरितार्थ किया है
- वर्ष 2030 तक रेलवे डीजल के उपयोग को शून्य कर विदेशी मुद्रा बचाएगी
- वर्ष 2026-27 के बजट में गुजरात की रेलवे परियोजनाओं के लिए 17,366 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर देश के सुदूरवर्ती मानव तक विकास पहुँचाया
- सरकार 'इकोनॉमी तथा इकोलॉजी'; दोनों को साथ लेकर चल रही है, एलएनजी ट्रेन की शुरुआत क्लीन-ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम
- गुजरात के तेज औद्योगिक विकास के अनुरूप रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को भविष्योन्मुखी बनाया जा रहा है
- विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में भारतीय रेलवे देश के परिवहन की सुदृढ़ रीढ़ बनेगी

गांधीनगर : भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा, कार्यक्षमता और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के करकमलों से साबरमती में 1,542 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न अत्यंत महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का रविवार को लोकार्पण, शिलान्यास और ट्रेन का प्रस्थान संपन्न किया गया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण-शिलान्यास के अवसर पर कहा, "आज हम आत्मबल तथा सत्य के प्रयोगों की भूमि साबरमती की धरती पर खड़े हैं, जहाँ महात्मा गांधी ने आश्रम स्थापित कर देश की स्वतंत्रता के आंदोलन का केन्द्र बनाया था। बापू ने इसी धरती पर सत्याग्रह, सादा जीवन, ग्रामीण विकास और खादी के प्रयोग किए थे। बापू की इस भूमि को नमन है।"

साबरमती रेलवे स्टेशन के बदले हुए स्वरूप के संबंध में अपने पुराने संस्मरणों को ताजा करते हुए उन्होंने कहा, "मैं पहले कई बार दिल्ली से आते समय साबरमती रेलवे स्टेशन पर उतरा हूँ... कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि 80 के दशक में जिस साबरमती स्टेशन से रिक्शा पकड़ने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, उसी साबरमती स्टेशन का ऐसा कायाकल्प हुआ है। साबरमती स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और कनेक्टिविटी की दृष्टि से अनेक परिवर्तन हुए हैं। यहाँ से मेट्रो रेल, बस स्टेशन और बुलेट ट्रेन स्टेशन तक पहुँचने की सुविधा विकसित हुई है।" उन्होंने जोड़ा, "मैं इसके लिए पश्चिम अहमदाबाद के लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ।"

देश में रेलवे क्षेत्र में स्थापित हो रहे आत्मनिर्भरता के नए आयामों एवं शक्तिशाली लोकोमोटिव के बारे में उन्होंने कहा कि एक ऐसा इंजन, जो 12,000 हॉर्स पावर की ट्विन सेक्शन क्षमता के साथ लगभग 600 ट्रकों के बराबर माल अकेले खींच सकेगा। पहले दो लोकोमोटिव लगाने पड़ते थे, अब एक ही WAG-12 यह काम कर सकता है। यह देश को रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुँचाएगा। उन्होंने कहा, "एक युवा इंजीनियर ने मुझे बताया कि इस इंजन की लागत का 94 प्रतिशत काम भारत में हुआ है, जिसे हम 3 वर्ष में 100 प्रतिशत कर देंगे।" शाह ने जोड़ा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है, जिन्होंने 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' का विजन दिया और रेलवे ने उसे चरितार्थ किया है।

देश की प्रथम एलएनजी ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर रेलवे के ग्रीन एनर्जी संकल्प तथा डीजल-मुक्त भविष्य की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2015-16 में रेलवे 293 करोड़ लीटर डीजल का उपयोग करती थी। यह डीजल उपयोग वर्ष 2024-25 में घटकर 108 करोड़ लीटर हो गया है और वर्ष 2030 तक इसे शून्य कर हम भारत की विदेशी मुद्रा बचाएंगे। विद्युतीकरण वर्ष 2010-11 में प्रतिवर्ष केवल 75 किलोमीटर होता था, जबकि वर्ष 2023-24 में एक ही वर्ष में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ है। 75 से सीधे 7,000 किलोमीटर की छलांग देखने को मिली है।

गुजरात को मिले रेलवे बजट की पूर्ववर्ती सरकारों के साथ तुलना करते हुए अमित शाह ने कहा कि यदि केवल गुजरात के रेलवे बजट की बात करें, तो वर्ष 2009 से 2014 के बीच 5 वर्षों में केवल 589 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि केवल वर्ष 2026-27 के बजट में गुजरात को 17,366 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रसेवा एवं जन कल्याण के 25 वर्ष के सफल कार्यकाल के अवसर पर देशभर में 'सेवा संकल्प अभियान' चल रहा है। प्रधानमंत्री ने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर देश के सुदूरवर्ती मानव तक विकास पहुँचाया है। अनुच्छेद 370 को समाप्त करना, आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक नीति जैसे असंभव लगने वाले कार्य प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अथक परिश्रम से साकार हुए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करकमलों से देश की प्रथम एलएनजी संचालित ट्रेन की शुरुआत के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम रेलवे तथा अहमदाबाद मंडल के लिए यह गौरवपूर्ण अवसर है। क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी की दिशा में यह पहल एक बड़ा कदम सिद्ध होगी, जो ईंधन खर्च कम करने के साथ कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में सहायक होगी। सरकार 'इकोनॉमी और इकोलॉजी'; दोनों को साथ लेकर चल रही है। रेलवे में 99 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी पहलें रेलवे को आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल बना रही हैं।

उन्होंने जोड़ा कि गुजरात के तेज औद्योगिक विकास के अनुरूप रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को भविष्योन्मुखी बनाया किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अलावा 5 वंदे भारत, 1 अमृत भारत और 1 नमो भारत ट्रेन की भेंट मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत राज्य के 87 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है और 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स प्रगत्याधीन हैं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 'विकसित भारत-2047' के संकल्प को साकार करने में भारतीय रेलवे सुरक्षा एवं गति के साथ देश के परिवहन की सुदृढ़ रीढ़ बनेगी।

कार्यक्रम के दौरान महानुभावों द्वारा लोकोमोटिव शेड में प्रदर्शनी देखी गई, लोको इंजन ट्रेन का निरीक्षण किया गया तथा लोकोमोटिव को फ्लैग ऑफ किया गया।

कार्यक्रम के आरंभ में डीआरएम, अहमदाबाद वेद प्रकाश ने स्वागत संबोधन किया। समग्र कार्यक्रम के अंत में पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा सभी मंचस्थ महानुभावों, उपस्थित नागरिकों तथा मीडियाकर्मियों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया गया।

इस लोकार्पण समारोह में राज्य मंत्री मती दर्शनाबेन वाघेला, अहमदाबाद के महापौर हितेशभाई बारोट, सांसद हसमुखभाई पटेल, साबरमती के विधायक डॉ. हर्षदभाई पटेल सहित अहमदाबाद तथा गांधीनगर क्षेत्र के विधायक, पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य महानुभाव उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से साबरमती में स्थापित अत्याधुनिक WAG-12 लोकोमोटिव मैंटेनेंस शेड का लोकार्पण किया गया है। 12,000 हॉर्स पावर क्षमता वाले 300 हाई-हॉर्स पावर विद्युत इंजनों के विश्वस्तरीय वैज्ञानिक रखरखाव के लिए तैयार किया गया यह शेड देश में भारी एवं लंबी मालगाड़ियों के संचालन को नई गति तथा विश्वसनीयता प्रदान करेगा।

इसके साथ ही साबरमती–कलोल–भांडू मोटीदाऊ तथा साबरमती–साणंद–जखवाडा रेलखंड पर 118.83 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई 122.57 किलोमीटर लंबी ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग (एबीएस) प्रणाली भी राष्ट्र को समर्पितण की गई है। यह प्रणाली ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने के साथ लाइन क्षमता तथा समयपालन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी।

रेल यात्रा को अत्यंत सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से अहमदाबाद मंडल के 404 किलोमीटर लंबे रेलखंड (अहमदाबाद–पालनपुर और अहमदाबाद–सामखियाळी) पर 411 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली स्वदेशी मानक 'कवच' प्रणाली का शिलान्यास संपन्न हुआ है। यह आधुनिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली मानवीय भूलों को कम करने तथा ट्रेनों की आमने-सामने या पीछे से होने वाली टक्करों को रोकने में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

इसके अलावा अहमदाबाद क्षेत्र में भविष्य की यात्रा तथा सरखेज–धोलेरा औद्योगिक कनेक्टिविटी को गति देने के लिए 313.27 करोड़ रुपए की लागत से मार्च 2028 तक पूर्ण होने वाले 21 किलोमीटर लंबे साबरमती–सरखेज रेलवे लाइन के डबलिंग कार्य का भी शिलान्यास किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में क्रांतिकारी पहल करते हुए मुख्य अतिथि द्वारा ड्राइविंग पावर कार (डीपीसी) में 40 प्रतिशत तक एलएनजी का उपयोग करने वाली भारत की सर्वप्रथम ड्युअल-फ्यूल एलएनजी ट्रेन तथा शक्तिशाली WAG-12 विद्युत लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीजल की बचत और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी करने वाली यह हरित पहल भारतीय रेलवे की कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता को साकार करती है।

अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में पारदर्शिता की मांग, ड्राफ्ट रिपोर्ट की समीक्षा समिति में एफआईपी को शामिल करने की अपील

मुंबई। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट को लेकर अब फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने पारदर्शिता और तकनीकी विशेषज्ञता से जुड़े सवाल उठाए हैं। एफआईपी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से आग्रह किया है कि यदि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) की तैयार की जा रही ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्ट की स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा के लिए कोई समिति गठित की जाती है, तो उसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स को भी औपचारिक रूप से शामिल किया जाए। संगठन का कहना है कि पेशेवर पायलटों का तकनीकी दृष्टिकोण दुर्घटना की परिस्थितियों और संभावित कारणों के मूल्यांकन में उपयोगी हो सकता है।

एफआईपी के अध्यक्ष कैप्टन सी.एस. रंधावा ने इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के समक्ष अपनी मांग रखी है। फेडरेशन ने कहा है कि उसे जानकारी मिली है कि सरकार या मंत्रालय की ओर से एएआईबी की ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्ट को सार्वजनिक या अंतिम रूप दिए जाने से पहले किसी स्वतंत्र समिति से उसकी समीक्षा कराने पर विचार किया जा रहा है। एफआईपी ने आग्रह किया है कि यदि ऐसा कोई समीक्षा तंत्र बनाया जाता है तो उसमें संगठन को स्वतंत्र तकनीकी हितधारक के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाए।

कैप्टन रंधावा के अनुसार, एफआईपी शुरुआत से ही इस दुर्घटना की जांच में विमान से जुड़ी तकनीकी परिस्थितियों की विस्तृत पड़ताल की मांग करता रहा है। उनका कहना है कि संगठन ने विमान की तकनीकी प्रणालियों, बिजली और ईंधन आपूर्ति से जुड़े संभावित पहलुओं को जांच के दायरे में रखने की मांग की थी। एफआईपी ने इस संबंध में पुष्कर राज सबरवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। संगठन का कहना है कि दुर्घटना के मूल कारणों तक पहुंचने के लिए उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों और परीक्षणों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण जरूरी है।

12 जून 2025 को एयर इंडिया की बोइंग 787-8 विमान सेवा एआई-171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास परिसर से जा टकराया। इस दुर्घटना में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हुई, जबकि जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी जान गई। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 260 रही। एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में दुर्घटना से संबंधित घटनाक्रम और उपलब्ध तथ्यों को दर्ज किया गया था, लेकिन दुर्घटना के अंतिम कारणों और सुरक्षा संबंधी निष्कर्षों के लिए अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार है।

दुर्घटना की जांच एएआईबी के नेतृत्व में चल रही है और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधित संस्थाओं की भागीदारी भी रही है। विमान बोइंग 787-8 होने के कारण अमेरिका की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) जैसी संस्थाओं की भूमिका भी जांच प्रक्रिया में रही है। एएआईबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच में बड़ी मात्रा में तकनीकी और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। जुलाई में केंद्र सरकार की ओर से शीर्ष अदालत को बताया गया था कि ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह में सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश की जा सकती है। अदालत ने यह भी दर्ज किया था कि एफआईपी अपनी तकनीकी टिप्पणियां एएआईबी को दे सकती है और ब्यूरो उन्हें जांच के दौरान आवश्यकतानुसार देख सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह भी बताया गया था कि याचिकाकर्ताओं की ओर से मांगे गए चार सिमुलेशन परीक्षण किए जा चुके हैं। इस मामले में अदालत स्वतंत्र और अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इनमें एक गैर सरकारी संगठन, एक कानून के छात्र और दुर्घटना में मारे गए पायलट कैप्टन सुमीत सबरवाल के पिता की याचिकाएं शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

एफआईपी का कहना है कि उसने जांच के दौरान उठाए गए तकनीकी सवालों पर अपनी ओर से इनपुट दिए हैं, लेकिन संगठन को अब तक औपचारिक बैठक के लिए नहीं बुलाया गया। कैप्टन रंधावा के मुताबिक, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से यह कहा गया था कि एफआईपी की ओर से उठाए गए मुद्दों को एएआईबी के समक्ष रखा जा सकता है और उन पर आवश्यक विचार किया जाएगा। इसके बावजूद एफआईपी का कहना है कि उसे अभी तक जांच प्रक्रिया में किसी औपचारिक बैठक या तकनीकी चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।

एफआईपी ने अब इस बात पर जोर दिया है कि यदि ड्राफ्ट रिपोर्ट के अंतिम रूप से पहले किसी स्वतंत्र समीक्षा समिति का गठन किया जाता है तो उसमें अनुभवी विमान चालकों और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की भागीदारी होनी चाहिए। संगठन के मुताबिक, विमान दुर्घटना की जांच में केवल दस्तावेजों और रिकॉर्ड का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि विमान संचालन, कॉकपिट प्रक्रियाओं, तकनीकी प्रणालियों और उड़ान के दौरान घटनाओं के क्रम को समझने के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय भी महत्वपूर्ण होती है।

इसी संदर्भ में एफआईपी ने मंत्रालय से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या ड्राफ्ट रिपोर्ट की समीक्षा के लिए स्वतंत्र समिति गठित की गई है या प्रस्तावित है। यदि समिति बनाई जाती है तो उसका गठन, कार्यक्षेत्र और सदस्यों की विशेषज्ञता क्या होगी, इस बारे में भी जानकारी मांगी गई है। एफआईपी ने यह भी अनुरोध किया है कि उसके पहले दिए गए तकनीकी सुझावों और प्रस्तुतियों को अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय औपचारिक रूप से विचार में लिया जाए।

दूसरी ओर, एएआईबी ने पहले स्पष्ट किया है कि विमान दुर्घटना की जांच एक तकनीकी और साक्ष्य आधारित प्रक्रिया है। फरवरी 2026 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया था कि एआई-171 दुर्घटना की जांच उस समय भी जारी थी और कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया था। एएआईबी ने यह भी कहा था कि अंतिम जांच रिपोर्ट जांच पूरी होने के बाद निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप जारी की जाएगी।

जांच के दौरान जुटाए गए कुछ संवेदनशील साक्ष्यों को सार्वजनिक करने को लेकर भी कानूनी प्रावधान लागू हैं। एएआईबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग और एयरबोर्न इमेज रिकॉर्डिंग जैसी सामग्री को बाहरी समिति या आम जनता के साथ साझा करने पर वैधानिक प्रतिबंध हैं। ब्यूरो ने विमान दुर्घटना जांच से संबंधित 2025 के नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि ऐसे संवेदनशील साक्ष्यों की गोपनीयता बनाए रखना जांच प्रक्रिया का हिस्सा है।

11.42 करोड़ की डिजिटल अरेस्ट ठगी में सीबीआई का शिकंजा, गुजरात से दो और आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद। गुजरात के 11.42 करोड़ रुपये के चर्चित 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हिमांशु प्रसाद और यूनिस बिस्वास के रूप में हुई है। सीबीआई के मुताबिक, जांच में दोनों की भूमिका ठगी की रकम को हासिल करने, उसे अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित कर उसकी लेयरिंग करने और फिर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचाने में सामने आई है। एजेंसी ने यह कार्रवाई देशभर में डिजिटल अरेस्ट और दूसरे संगठित साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की है।

सीबीआई के अनुसार, 'ऑपरेशन चक्र-6' के तहत डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में कार्रवाई को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान देश के 10 राज्यों में 22 स्थानों पर एक साथ तलाशी ली गई। गुजरात में की गई कार्रवाई इसी नेटवर्क से जुड़े 11.42 करोड़ रुपये के मामले की जांच का हिस्सा थी। एजेंसी का कहना है कि साइबर अपराधियों के ऐसे गिरोह अलग-अलग राज्यों में बैठे लोगों को निशाना बनाते हैं और पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों, दूरसंचार विभाग या अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारी बनकर उन्हें डराते हैं। इसके बाद पीड़ितों को जांच, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध सिम कार्ड अथवा बैंक खातों से जुड़े मामलों में फंसाने की धमकी देकर बड़ी रकम ट्रांसफर कराई जाती है।

गुजरात के इस मामले में पीड़ित को कथित तौर पर करीब तीन महीने तक 'डिजिटल अरेस्ट' की स्थिति में रखा गया। साइबर अपराधियों ने खुद को पुलिस और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अधिकारी के रूप में पेश किया। आरोपियों ने पीड़ित को यह विश्वास दिलाया कि वह किसी गंभीर कानूनी या वित्तीय मामले में फंस गया है और जांच से बचने के लिए उसे उनके निर्देशों का पालन करना होगा। इसी डर और दबाव के बीच पीड़ित से अलग-अलग खातों में कुल 11.42 करोड़ रुपये ट्रांसफर कराए गए।

सीबीआई की जांच में हिमांशु प्रसाद और यूनिस बिस्वास की भूमिका ठगी की रकम की आवाजाही से जुड़ी पाई गई। एजेंसी के अनुसार, दोनों ने कथित तौर पर एक कंपनी के बैंक खाते का इस्तेमाल पीड़ित से ठगी गई रकम में से 2.5 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए किया। इसके बाद इस रकम को गिरोह के अन्य सदस्यों से जुड़े कई बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि रकम को एक खाते से दूसरे खाते में भेजने का उद्देश्य उसके वास्तविक स्रोत और अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचने वाली मनी ट्रेल को जटिल बनाना था। जांचकर्ताओं ने बैंक खातों के लेनदेन, संदिग्ध रकम के ट्रांसफर और उससे जुड़े डिजिटल साक्ष्यों का विस्तृत वित्तीय तथा तकनीकी विश्लेषण किया। इसी विश्लेषण से आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली। सीबीआई ने तलाशी के दौरान कई बैंकिंग दस्तावेज, खातों से संबंधित रिकॉर्ड, मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जब्त की है। एजेंसी के मुताबिक, जब्त डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच की जा रही है। इनमें मौजूद चैट, संदेश, दस्तावेज और अन्य सामग्री से आरोपियों की कथित भूमिका तथा गिरोह के दूसरे सदस्यों के साथ उनके संपर्कों की जानकारी मिलने की उम्मीद है। सीबीआई के अनुसार, जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट समेत दूसरे साइबर अपराधों से हासिल रकम को निकालने और आगे पहुंचाने के लिए बैंक खातों के इस्तेमाल में शामिल थे। जांच में एपीके फाइलों से जुड़े पहलुओं का भी पता चला है। साइबर अपराधों में एपीके यानी एंड्रॉयड पैकेज किट फाइलों का इस्तेमाल कई बार लोगों के मोबाइल फोन में संदिग्ध या नुकसान पहुंचाने वाले एप्लिकेशन इंस्टॉल कराने के लिए किया जाता है। हालांकि इस मामले में जब्त उपकरणों से मिली सामग्री का फोरेंसिक परीक्षण अभी जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही अपराध के पूरे तकनीकी नेटवर्क की तस्वीर स्पष्ट होगी।

'डिजिटल अरेस्ट' साइबर अपराध का ऐसा तरीका है जिसमें अपराधी वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई, ईडी, ट्राई, आरबीआई अथवा किसी अन्य सरकारी संस्था का अधिकारी बताते हैं। पीड़ित को बताया जाता है कि उसके नाम से कोई आपराधिक मामला दर्ज है या उसके बैंक खाते का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों में हुआ है। इसके बाद उसे लगातार निगरानी में रहने, किसी से बात नहीं करने और जांच पूरी होने तक ऑनलाइन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। कई मामलों में अपराधी पीड़ित को वीडियो कॉल पर घंटों या दिनों तक जुड़े रहने के लिए मजबूर करते हैं और इसी दौरान बैंक खातों से रकम ट्रांसफर कराते हैं।

गुजरात के इस मामले में भी कथित तौर पर यही तरीका अपनाया गया। पीड़ित को लंबे समय तक मानसिक दबाव में रखने के बाद करोड़ों रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराए गए। बड़ी रकम होने के कारण सीबीआई ने लेनदेन की प्रत्येक कड़ी का विश्लेषण किया। एजेंसी का ध्यान केवल उस खाते तक सीमित नहीं रहा जिसमें सबसे पहले रकम पहुंची, बल्कि उसके बाद रकम किन खातों में गई, किन लोगों या कंपनियों से उनका संबंध था और किस स्तर पर पैसे निकाले या स्थानांतरित किए गए, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सीबीआई का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में अपराधी अब केवल एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहते। ठगी का शिकार किसी दूसरे राज्य में रहने वाला व्यक्ति हो सकता है, जबकि फोन करने वाला आरोपी किसी तीसरे राज्य में और रकम प्राप्त करने वाला बैंक खाता किसी चौथे राज्य में हो सकता है। इसी वजह से ऐसे मामलों की जांच में अलग-अलग राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑपरेशन चक्र-6 के तहत की जा रही कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे अंतरराज्यीय नेटवर्क की पहचान करना और उनके वित्तीय तथा तकनीकी ढांचे को सामने लाना है। एजेंसी ने बताया कि उसने अलग-अलग राज्यों से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के कई मामलों को अपने हाथ में लिया है। इनमें से चार मामलों में पिछले 30 दिनों के दौरान बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने 22 राज्यों में 142 स्थानों पर छापेमारी की और 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन कार्रवाइयों के दौरान प्राप्त डिजिटल उपकरणों और वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर साइबर अपराध के नेटवर्क की आगे की जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम किन माध्यमों से एक खाते से दूसरे खाते तक पहुंचाई गई और इसमें कितने लोग तथा संस्थाएं शामिल थीं।

देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी, यूपी-बिहार से महाराष्ट्र तक बरसेंगे बादल

नई दिल्ली। सितंबर के अंतिम दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी है, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों के साथ महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर बना निम्न दबाव तंत्र कमजोर होकर आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसके प्रभाव से मध्य और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मौसम सक्रिय बना हुआ है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी और उससे जुड़े क्षेत्रों में भी मौसम प्रणाली विकसित होने से आने वाले दिनों में पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। समुद्री क्षेत्र में बने सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावना को देखते हुए संबंधित इलाकों में मौसम पर नजर रखी जा रही है।

राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने का अनुमान है। आईएमडी के दिल्ली-एनसीआर पूर्वानुमान में 28 सितंबर के लिए स्थानीय स्तर पर मौसम की निगरानी जारी है। आसमान में आंशिक बादल रह सकते हैं और तापमान में बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगले कुछ दिनों में भी दिल्ली में मौसम मुख्य रूप से बादलों और धूप के बीच रहने का अनुमान है। आईएमडी के दिल्ली-एनसीआर पूर्वानुमान में 28 सितंबर से आगे के दिनों के लिए भी स्थानीय मौसम की स्थिति दर्ज की गई है।

उत्तर प्रदेश में मौसम का असर कई इलाकों में दिखाई दे सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई थी और 27 सितंबर के आईएमडी बुलेटिन में विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर चेतावनी दी गई थी। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। पूर्वी हिस्सों में भी स्थानीय स्तर पर बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

ऐसे में किसानों और आम लोगों को मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

बिहार और झारखंड में भी मौसम सक्रिय रहने के संकेत हैं। कई इलाकों में बादल छाए रहने के साथ बारिश या गरज-चमक की गतिविधियां हो सकती हैं। झारखंड के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार में भी अगले कुछ दिनों के दौरान अलग-अलग स्थानों पर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं की स्थिति में खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी मौसम की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के आसपास विकसित हो रहे मौसम तंत्र का असर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर पड़ सकता है। ओडिशा के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों और मछुआरों को स्थानीय मौसम चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

मध्य भारत में भी बारिश पूरी तरह थमती नजर नहीं आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी आने वाले दिनों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश और गरज-चमक का दौर देखने को मिल सकता है। इससे तापमान में गिरावट और वातावरण में नमी बढ़ने की स्थिति बन सकती है।

महाराष्ट्र और गुजरात में भी कई जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान है। गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय और मध्य भागों में स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण अचानक तेज बारिश की स्थिति बन सकती है। शहरों में तेज बारिश होने पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।

उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में मौसम विशेष रूप से सक्रिय रहने की संभावना है। उत्तराखंड में 28 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ गरज-चमक भी हो सकती है। आईएमडी के चारधाम पूर्वानुमान में देहरादून के लिए 28 सितंबर को बादल छाए रहने और बारिश या गरज के साथ बौछारों की संभावना दर्ज की गई है।

हिमाचल प्रदेश में भी गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए यात्रा करने वालों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने की जरूरत है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के दौरान सड़क और यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।

पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना बनी हुई है। आईएमडी ने 28 सितंबर के लिए दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और गरज-चमक की चेतावनी भी दर्ज की है।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक सितंबर के अंतिम दिनों में मानसूनी गतिविधियों के साथ अलग-अलग निम्न दबाव प्रणालियों और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों का प्रभाव कई राज्यों में दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि एक ही समय में देश के एक हिस्से में भारी बारिश तो दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत साफ मौसम देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी मौसम में क्षेत्रीय स्तर पर उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।

बारिश के इस दौर को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। गरज-चमक के दौरान पेड़, बिजली के खंभे और खुले स्थानों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग सड़क की स्थिति और स्थानीय प्रशासन की सलाह की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। वहीं किसानों के लिए भी बारिश के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए खेतों में जरूरी कृषि कार्यों की योजना बनाना उपयोगी रहेगा। फिलहाल देश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर जारी है और सितंबर के अंतिम दिनों में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज लोगों को प्रभावित करता रहेगा।